Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-02 16-31 जनवरी, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'घटिया राजनीति कर रही कांग्रेस'

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025

आप-दा नहीं सहेंगे... बदल के रहेंगे

संविधान गौरव अभियान पर विशेष

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 25 दिसंबर, 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया मुख्यालय (नई दिल्ली) में 25 दिसंबर, 2024 को क्रिसमस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 25 दिसंबर, 2024 को एनडीए नेताओं की बैठक में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं अन्य वरिष्ठ एनडीए नेतागण

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 29 दिसंबर, 2024 को भाजपा संगठन पर्व कार्यशाला में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

नई दिल्ली में 04 जनवरी, 2025 को सुषमा भवन एवं पशु चिकित्सालय का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है...वो किसी आप-दा से कम नहीं है। ये ऐहसास आज दिल्लीवालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब...

08 दिल्ली का वोटर 'दिल्ली को' आप-दा से मुक्त करने की ठान चुका है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के...

09 भाजपा सत्ता में आई तो दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू...

28 देश के लिए जीने वाला हर बच्चा और युवा 'वीर बालक' है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया। तीसरे वीर...

30 मनमोहन सिंह जी के निधन पर घटिया राजनीति कर रही कांग्रेस : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18...

ब्लॉग

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी / **नरेन्द्र मोदी** 18

लेख

प्रखर राष्ट्रवादी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर / **डॉ. वीरेंद्र कुमार** 10

बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर: अन्याय, अपमान से न्याय व सम्मान की यात्रा / **अर्जुन राम मेघवाल** 12

प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ है / **लाल सिंह आर्य** 14

कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माता का अपमान / **बृजलाल** 17

बाबा साहेब और उनके नाम पर की जा रही गांधी परिवार की कुत्सित राजनीति / **डॉ. भोला सिंह** 22

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बाबा साहेब के विजन को जमीन पर उतारा / **गुरु प्रकाश** 24

भाजपा डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण की सबसे सच्ची संरक्षक है / **अभिनव प्रकाश** 26

अन्य

किसानों को किफायती दरों पर डीएपी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु एनबीएस सब्सिडी के परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मिली मंजूरी 29

मोदी स्टोरी 31

कमल पुष्प 31

डॉ. सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों से उबरकर ऊंचाइयों को प्राप्त करना सिखाता है: नरेन्द्र मोदी 32

'मन की बात' 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

X

नरेन्द्र मोदी

आज देश का युवा असंभव को संभव बना रहा है। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी युवाशक्ति 'विकसित भारत' का सपना जरूर साकार करेगी।

(12 जनवरी, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ाकर लूट मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई-बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गये। केजरीवाल ने यूपी-बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी।

(09 जनवरी, 2025)

अमित शाह

चाहे ड्रग तस्करी हो, स्मगलिंग हो, मानव तस्करी हो या कोई अन्य अपराध; 'भारतपोल' के माध्यम से राज्य की पुलिस 195 देशों से सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

(07 जनवरी, 2025)

राजनाथ सिंह

आज साल 2025 के पहले ही दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर कई बड़े अहम निर्णय किए गए हैं। सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी देकर और फसल बीमा योजना का विस्तार करके किसानों को बड़ी सौगात दी है। नये साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला फैसला ही किसानों को समर्पित है। प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय किसान कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। (01 जनवरी, 2025)

बी.एल. संतोष

आज एक विशेष अभियान के तहत 4.5 लाख से अधिक सदस्य बनाने के लिए महाराष्ट्र भाजपा टीम को बधाई! बंगाल भाजपा ने भी आज 50 हजार से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाए। बूथ स्तर पर काम करने वाले उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इसे संभव बनाया।

(05 जनवरी, 2025)

पीयूष गोयल

मोदी सरकार का शासन मॉडल - समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है। वर्ष 2011-12 में जो गरीबी दर 22 प्रतिशत थी, वह अब घटकर 2023-24 में 5 प्रतिशत हो गयी है, भारत में हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है! (04 जनवरी, 2025)

संपादकीय

'आप-दा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे'

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होते ही आम आदमी पार्टी (आप) के कुशासन के अंत की राह देख रही जनता में उत्साह का संचार हुआ है। आप सरकार के दस वर्षों का दौर कुशासन, व्यापक भ्रष्टाचार, झूठे वायदों और पंगु शासन का पर्याय बना रहा। परिणामतः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, स्वच्छता और पेयजल जैसी आधारभूत समस्याएं राजधानी में दिनोंदिन भयावह होती गयीं। आप नेता अरविंद केजरीवाल, जो अपने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हुए हैं, आज देश में सिद्धांतहीन एवं अवसरवादी राजनीति का एक शर्मनाक चेहरा बन गए हैं। उन्होंने न केवल राजनैतिक गिरावट में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं बल्कि भ्रष्टाचार, कुशासन एवं अनैतिक राजनीति का बेशर्मी के साथ महिमामंडन करने में महारत प्राप्त की है। 'आप' सरकार का कोई भी आकलन, पिछले दस साल के इसके कुशासन को एक 'आपदा' की ही संज्ञा देगा। हर क्षेत्र में पूरी तरह से असफल आप सरकार पिछले दशक में दिल्ली के लिए भयावह आपदा साबित हुई है। दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आप सरकार की संवेदनहीनता को गिनाते हुए कहा कि जब दिल्ली ऑक्सीजन एवं दवाइयों के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उनका ध्यान 'शीशमहल' पर था। परिणाम यह है कि दिल्ली की जनता आज 'आप-दा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे' का समर्थन कर रही है।

> आप सरकार के दस वर्षों का दौर कुशासन, व्यापक भ्रष्टाचार, झूठे वायदों और पंगु शासन का पर्याय बना रहा

अपने पुराने पापों को छिपाने के लिए कांग्रेस जब संविधान और 'भारत रत्न' बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम लेती है तो सच में बड़ा आश्चर्य होता है। कांग्रेस द्वारा संविधान पर निरंतर हमले तथा बाबा साहेब तथा उनकी विरासत के अपमान करने का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। कांग्रेस द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार संविधान को किस प्रकार से बदला गया, देश अभी तक भूला नहीं है। संविधान की आत्मा और इसके मूल्यों को कांग्रेस के तानाशाही नेतृत्व द्वारा बार-बार कुचला गया है। यहां तक कि कांग्रेस ने देश पर आपातकाल तक थोपा, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाया और 'मीसा' जैसे काले कानून बनाए। गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने एवं अस्थिर कर भारतीय संघवाद को खोखला करने का कांग्रेस का काला इतिहास रहा है। यहां तक कि किस प्रकार से अनेक बार केंद्र सरकार को गिराकर देश को राजनैतिक अस्थिरता में झोंका गया, सभी को मालूम है। परिवारवाद-वंशवाद में अटूट विश्वास रखने वाली कांग्रेस संविधान सम्मत लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों की तिलांजलि देकर केवल एक परिवार की दास बन चुकी है। इसका नेतृत्व संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा अपनी राह का रोड़ा मानकर अपमान करता रहा है और जब भी संभव हुआ उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस आज एकाधिकारवाद एवं तानाशाही के लिए जानी जाती है।

स्वतंत्रता काल से ही कांग्रेस का लोकतंत्र विरोधी चेहरा उजागर हुआ था, जब बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित अनेक विभूतियों को अपमानित कर दरकिनार किया जाने लगा। बाबा साहेब को निरंतर अपमान एवं तिरस्कार सहना पड़ा तथा अत्यंत निराशापूर्ण स्थिति में नेहरू कैबिनेट से त्यागपत्र देने को बाध्य हुए। संविधान निर्माता के रूप में उनके योगदान की उपेक्षा की गई तथा उन्हें कांग्रेस द्वारा न तो 'भारत रत्न' का सम्मान दिया गया और न ही उनके चित्र को संसद के केंद्रीय-कक्ष में स्थान दिया गया।

जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब बाबा साहेब को कृतज्ञ राष्ट्र ने 'भारत रत्न' से सुशोभित किया तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अथक प्रयासों से उनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब की विरासत को सम्मान देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, 'पंचतीर्थ' का विकास किया है, 'भीम एप' का शुभारंभ हुआ है तथा बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए मोदी सरकार कृतसंकल्पित है। आज जब जन-जन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा पर बरस रहा है, केंद्र एवं राज्यों की राजग सरकारें वंचित, शोषित, पीड़ित एवं समाज के कमजोर वर्गों के हित में निरंतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है: नरेन्द्र मोदी

दिल्ली में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 05 जनवरी, 2024 को दिल्ली के रोहिणी में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को देखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली का ये उत्साह, उमंग और हौसला अद्भुत है। दिल्ली सहित देशभर के लोग आने वाले 25 साल में 'विकसित भारत' की यात्रा के भागीदार बनने वाले हैं। उन्होंने कहा, "मैं दिल्लीवासियों से दिल्ली के उज्ज्वल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया हूं। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है...वो किसी आप-दा से कम नहीं है। ये ऐहसास आज दिल्लीवालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में एक ही आवाज़ गूंज रही है—आप-दा नहीं सहेंगे...बदल के रहेंगे!

भाजपा के प्रति जन-विश्वास

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा विकास के लिए समर्पित भाव से जन-जन का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए, देश भी भाजपा पर इतना विश्वास जता रहा है और बार-बार अवसर दे रहा है। उन्होंने कहा, "बीते वर्षों में दिल्ली के लोगों ने देखा है,

- **जब दिल्ली ऑक्सीजन और दवाओं के लिए जूझ रही थी, तब 'आप-दा' के नेता का ध्यान 'शीशमहल' पर था**
- **दिल्ली को ऐसी सरकार की जरूरत है जो सुने, परवाह करे और काम करे। केवल भाजपा ही इस सपने को पूरा कर सकती है**

नॉर्थ-ईस्ट में कमल खिला, ओडिशा में कमल खिला, अभी हाल में ही हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से चुना है। महाराष्ट्र ने भाजपा को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया है, दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया और अब मुझे विश्वास है, दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है!"

उन्होंने कहा कि दिल्ली नौजवानों के लिए नए भविष्य के निर्माण का शहर बने, इसके लिए भाजपा पूरे समर्पण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हम दिल्ली को दुनिया की एक ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। ये तभी हो सकता है, जब दिल्ली में केंद्र और राज्य, दोनों में भाजपा की सरकार काम करे।"

दिल्ली में केंद्र सरकार के विकास-कार्य

दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नमो रेल प्रोजेक्ट से लेकर दिल्ली और आसपास बन रही 6 और 8 लेन की सड़कें केंद्र सरकार बना रही है। वहीं दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। डीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसों की भरपूर मदद कर रही है।

दिल्ली के अशोक विहार में बनाए गए स्वाभिमान अपार्टमेंट का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने हर झुग्गी-झोपड़ी वालों से यह बताने का आग्रह किया कि उन्हें भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। वहीं कुशासन को लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा, "उन्हें ये देखकर दुःख होता है कि आप-दा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आप-दा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब है, दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। यही वजह है कि सामान्य नागरिक से लेकर लाखों दुकानदार, व्यापारी-कारोबारी सब राज्य सरकार से तंग आ चुके हैं।"

आप-दा गरीब की सुविधा को रोकती है

'शीशमहल' का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए एक अखबार की खबर का उल्लेख किया और कहा कि इस पर बजट से तीन गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। इसलिए आज हर दिल्लीवाला कह रहा है— आप-दा नहीं सहेंगे... बदल के रहेंगे! उन्होंने कहा, "जबसे मैंने, आप-दा का कच्चा-चिट्ठा खोला है, तबसे ये तिलमिलाए हुए हैं। इसलिए जब दिल्ली से आप-दा हटेगी, तो ही विकास और सुशासन का डबल इंजन आएगा।"

उन्होंने कहा कि आप-दा गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा को रोकती है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' हो, गरीबों के लिए पक्के घर बनाने हो या फिर पानी और सीवर की समस्या का समाधान, विकास के हर काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। उन्होंने कहा, "देशभर में करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं करोड़ों बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिलना तय हो चुका है, लेकिन आप-दा वाले, अभी भी अड़े हुए हैं कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं होने देंगे।"

उन्होंने कहा कि राजनीति में नीयत, निर्णय, नीति और निष्ठा का बहुत महत्व होता है, लेकिन आप-दा वालों की नीयत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, "जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना, ये इनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं।"

श्री मोदी ने कहा, "आप-दा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए हैं और झूठ फैला रहे हैं। वे दिल्ली वालों को डरा रहे हैं, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाने आया हूं कि भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें बेईमानों का जो ठेका है उनको निकाला जाएगा।" ■

दिल्ली का वोटर 'दिल्ली को' आप-दा से मुक्त करने की ठान चुका है: नरेन्द्र मोदी

अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपीं।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि झुग्गियों की जगह पक्के घर और किराए के घरों की जगह खुद के घर, वास्तव में एक नई शुरुआत का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को आवंटित घर आत्मसम्मान, स्वाभिमान और नई आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि वे उनके उत्सव और त्योहार का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं।

श्री मोदी ने कहा, "आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में लगा हुआ है।" उन्होंने कहा कि हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि 'विकसित भारत' में देश के हर नागरिक के पास पक्का घर हो। उन्होंने आगे कहा कि इस संकल्प को पूरा करने में दिल्ली की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए, केंद्र सरकार ने झुग्गियों को पक्के घरों से बदलने की योजना शुरू की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दो साल पहले उन्हें झुग्गीवासियों के लिए कालकाजी एक्सटेंशन में 3,000 से अधिक घरों का उद्घाटन करने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की कई पीढ़ियां बिना किसी उम्मीद के झुग्गियों में रहती थीं, वे पहली बार पक्के घरों में चले गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है और आज लोगों को लगभग 1,500 घरों की चाबियां दी गईं। उन्होंने कहा, "यह कदम स्वाभिमान अपार्टमेंट लोगों के आत्मसम्मान को और बढ़ाएगा।"

बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आप-दा से घिरी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आप-दा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आप-दा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला, ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग 'आप-दा' बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसका महिमामंडन भी करते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली का वोटर 'दिल्ली को' आप-दा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है— आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के ज़िम्मे हैं। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े-बड़े अस्पताल, बड़े-बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है, लेकिन यहां की आप-दा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है, उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है।

श्री मोदी ने कहा कि आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। 'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना' ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था।

उन्होंने कहा कि मैं तो दिल्लीवालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली 'आयुष्मान योजना' का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आप-दा सरकार को दिल्लीवालों से बड़ी दुश्मनी है। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आप-दा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे।

श्री मोदी ने कहा कि आपको याद रखना है जहां-जहां आप-दा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। उन्होंने कहा कि आप-दा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। ■

भाजपा सत्ता में आई तो दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 जनवरी, 2025 को आयोजित 'झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर राजधानी में लागू कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि भाजपा सरकार उनमें सुधार करेगी।

- श्री शाह ने यह वादा भी किया कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है, तो प्रत्येक झुग्गी-झोपड़ी निवासी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा।

- राजधानी की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग अब 'आप-दा' को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और यह दिल्ली के मुक्तिदाता बनेंगे।
- श्री शाह ने कहा कि स्वच्छ पानी, अच्छी शिक्षा एवं कचरा मुक्त शहर के बड़े-बड़े वादे करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने झुग्गीवासियों को गंदे पानी, वायु प्रदूषण, टूटी सड़कों और कचरे के साथ दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया है।
- झुग्गीवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए आप के खिलाफ लड़ने वाली दिल्ली भाजपा इकाई को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा, "हमारे नेता ने झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में कई रातें बिताईं हैं और आपकी सभी परेशानियों की एक सूची बनाकर प्रधानमंत्री को सौंपी हैं। हम इसे ध्यान में रखते हुए, अपना संकल्प पत्र लाएंगे।"
- श्री शाह ने कहा कि आप पार्टी दिल्ली में तबाही मचाने का काम कर रही है। जहां भारत ने पिछले दस सालों में तरक्की की है, वहीं दिल्ली की स्थिर बद से बदतर हो गयी है। उन्होंने कहा कि 'आप-दा' की वजह से दिल्ली नरक बन गई है।
- श्री शाह ने कहा कि झूठ, विश्वासघात एवं वादों से मुकरना श्री केजरीवाल के गुण हैं। आप नेता दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जरूरी शौचालय बनाने के बजाय 'शीशमहल' बनवा रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने गरीबों को घर, राशन, सस्ती दवाइयां, लोन एवं रसोई गैस दी है, जबकि श्री केजरीवाल ने दिल्ली में उनके लिए कुछ नहीं किया। ■

'कहते थे सरकारी बंगला नहीं लेंगे, जनता के पैसों से लिया शीशमहल'

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की स्मृति में नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल ब्लाक 'सुषमा भवन' का उद्घाटन और मोती बाग में पशु चिकित्सालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिल्ली के विकास के लिए किये गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के शीशमहल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, देश की पूर्व विदेश मंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के जीवन, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण और उनके नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शहरी विकास के लिए एक सशक्त नीतिगत ढांचा तैयार किया, जिससे शहरों का समग्र विकास संभव हो सका।

श्री शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को विकास से वंचित रखा गया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए शीशमहल खड़ा कर लिया एवं वह सारी सुविधाएं हासिल कर लीं, जिनसे उन्होंने राजनीति में आने से पहले परहेज किया था।

उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल राजनीति में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि वे सरकारी गाड़ी और सरकारी बंगला नहीं लेंगे और एक नई तरह की राजनीति करेंगे लेकिन अब उन्होंने 50 हजार गज पर दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपये से शीशमहल बनवाया। इस शीशमहल में 6 करोड़ रुपये के डिजाइनर मार्बल, 6 करोड़ रुपये के मोटर वाले पर्दे, 70 लाख रुपये के ऑटोमेटिक दरवाजे, 64 लाख रुपये के स्मार्ट टीवी, 50 लाख रुपये के कालीन और 36 लाख रुपये के सजावटी खंभे किसके पैसे से लगाए गए? केजरीवाल ने अपने परिवार के लिए 15 करोड़ रुपये का वाटर सिस्टम लगाया, जबकि दिल्ली की जनता को पानी तक ठीक से नहीं मिल पा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनकर शराब घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार, दवाओं के दामों पर करप्शन, सोलर स्ट्रीट के नाम पर घोटाला, सीसीटीवी कैमरों में भ्रष्टाचार, बसों की खरीदारी में घोटाला और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीशमहल बनाने का काम किया। केजरीवाल भाजपा पर जो आरोप लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, मगर इसका फैसला जनता करेगी। ■

प्रखर राष्ट्रवादी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

डॉ. वीरेंद्र कुमार

देश अपने संविधान का 75वें वर्ष का उत्सव माना रहा है। यह समय 'संविधान के सम्मान' का काल है। यह संविधान की एक ऐतिहासिक यात्रा है, जिसने कई बाधाओं और चुनौती को दूर करते हुए अपने को सशक्त रूप में स्थापित किया है। यह एक उपलब्धि है, क्योंकि भारत के साथ स्वतंत्र होने वाले अन्य देशों के अधिकतर संविधान की औसत आयु 15 या 17 वर्ष ही रही है। भारत एक सफल लोकतंत्र के श्रेणी में खड़ा हुआ है। इस सफलता के समय उन संविधान निर्माताओं का स्मरण करना आवश्यक है, जिसमें डॉ. अम्बेडकर एक प्रतीक के रूप में सभी का प्रतिनिधित्व करते है। संविधान का सम्मान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का सम्मान है।

बाबा साहेब संविधान के सूत्रधार हैं। डॉ. अम्बेडकर में आध्यात्मिकता है। वे मानते हैं कि सभी में परम चैतन्य आत्मा व्याप्त है। संविधान के प्रणयन में योगदान है। डॉ. अम्बेडकर का संविधान 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की अवधारणा पर आधारित है। यदि ऐसा नहीं होता, तो इतना सुन्दर प्रस्तावना निकलकर नहीं आती। हम सब जानते है कि भारत के संविधान की आत्मा उसके प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना ही भारत का राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति ही अभीष्ट लक्ष्य है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल भावना या प्राण तत्व है।

डॉ. अम्बेडकर पहली बार संविधान सभा में 17 दिसबर 1946 को बोले थे और अंतिम बार 25 नवम्बर, 1949 को बोले थे, जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। हम सभी भाषण का तो उल्लेख नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में 25 नवम्बर की टिप्पणी सभी का सार है, यह भाषण बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है जिसमें वे संविधान की कार्य प्रणाली, जनतंत्र के सफल होने की पूर्व दशाएं और असफल होने की आशंकाएं बताई हैं।

वे संविधान सभा का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को समवेत हुई थी और पूरा संविधान दो वर्ष ग्यारह महीने और सत्रह दिन में तैयार हुआ था, जिसके लिए संविधान सभा के कुल सत्रह सत्र हुये। इन सत्रह सत्रों में से प्रथम छह सत्र लक्ष्यमूलक संकल्प पारित करने और मूलाधिकार विषयक, संघ संविधान विषयक, संघ की शक्तियों, प्रान्तीय संविधान विषयक, अल्पसंख्यक-वर्ग विषयक तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों विषयक समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने में लगे। सातवें, आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें सत्रों में संविधान के प्रारूप पर विचार हुआ। संविधान सभा के इन ग्यारह सत्रों में 165 दिन लगे। इनमें से सभा ने 114 दिन संविधान के पारूप पर विचार करने में लगाये। ये तथ्य वे स्वयं सदन के पटल पर रखे थे।

बाबा साहेब की संविधान के वास्तुकार के रूप में भूमिका व्यापक है, क्योंकि प्रारूप समित के अध्यक्ष है। एक प्रकार से संविधान के पर्याय हैं। लगभग सभी अनुच्छेद कोई न कोई उत्तर या सुझाव हैं, लेकिन कुछ योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है।

राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के एकीकरण में उनके योगदान के स्मरण के लिए केवल एक शब्द ही पर्याप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि "India That is Bharat shall be union of state", भारत 'राज्यों का संघ' होगा। यह शब्द भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके राजनीतिक जीवन को वैचारिक दृष्टि सामान्य तौर पर दो अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवस्था वह है जहां पर डॉ. अम्बेडकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में हैं। उनके चिंतन के केंद्र में अस्पृश्य समाज का हित है। अपने चिंतन की दूसरी अवस्था में, जब वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते है, तब उनके विचारों में राष्ट्रीयता दिखती है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र का एकीकरण ही उनके चिंतन का आयाम बनता है। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता, भाषा, केंद्र के पास शक्तियों जैसे विषयों पर मुखर और स्पष्ट हैं, जिसमें वह एक सशक्त भारत चाह रहे हैं। विधि मंत्री के रूप में पाकिस्तान से अपने समाज के वापस आने का आह्वान हो या इस्लाम न स्वीकार करने की सलाह हो, वे राष्ट्रीय हित को ध्यान देते हैं। यहां पर डॉ. अम्बेडकर एक युगपुरुष नेता के रूप में उभरते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था। डॉ. अम्बेडकर प्रखर राष्ट्र भक्त थे, क्योंकि उनके सम्पूर्ण चिंतन का केंद्रबिंदु भारत व भारत का भविष्य ही था। लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से किया गया

> **राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के एकीकरण में उनके योगदान के स्मरण के लिए केवल एक शब्द ही पर्याप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि "India That is Bharat shall be union of state", भारत 'राज्यों का संघ' होगा। यह शब्द भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करता है**

उनका शोध भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही था और कोलंबिया विश्वविद्यालय से किये गये उनके शोध के केंद्र में भी भारत के ट्रेड/व्यापार/वाणिज्य के बारे में पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर कहीं भी रहे हों, लेकिन उनके हृदय और मस्तिष्क में भारत ही बसता और धड़कता था। इसलिए जब हम डॉ. अम्बेडकर को समग्रता में देखते है तो हमें उनके जीवन की महानता के दर्शन होते हैं। प्रत्येक भारतीय को वे एक सन्देश देते है, "We are Indian Firstly and Lastly" ये पंक्ति पढ़ने में जितनी सामान्य दिखती है इसका अर्थ उतना ही गहरा है।

डॉ. अम्बेडकर देश की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करने वाली शक्तियों के सदैव खिलाफ थे। भारत विभाजन से पूर्व उन्होंने पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ़ इंडिया में वे भारत विरोधी षड्यंत्रों को उजागर करते है। वे अपने भाषणों में कहते हैं कि यदि पाकिस्तान बनाना ही है तो फिर 'टोटल एक्सचेंज ऑफ़ मुस्लिम पॉपुलेशन' यानी वे मुस्लिम जनसंख्या को पूरी तरह से पाकिस्तान भेजने की वकालत करते हैं।

भारत विभाजन के बाद हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय नहीं किया था और उसके द्वारा और पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचारों की लगातार घटनाओं से डॉ. अम्बेडकर जी बहुत दुःखी थे। हैदराबाद और पाकिस्तान में दलितों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। डॉ. अम्बेडकर हैदराबाद के निजाम को भारत का दुश्मन बताते हुए वहां के दलितों को निर्देश देते है कि वे उसका साथ न दें। यहां प्रत्यक्ष रूप से उनका राष्ट्रवाद झलकता है।

यह सहज आशंका भारतीय और पाश्चात्य जगत में था कि स्वतंत्र भारत कब तक स्वतंत्र रहेगा। यह प्रश्न डॉ. अम्बेडकर के समक्ष भी था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण इसका उत्तर भी जानना आवश्यक था। इसलिए डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि 26 जनवरी, 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा, उसकी स्वाधीनता का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा या उसको फिर खो देगा?

दूसरी आशंका डॉ. अम्बेडकर का भारतीय संविधान के भविष्य को लेकर है। वे कहते हैं कि जब भारत 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र हो जायेगा, तो उसके इस लोकतंत्रात्मक संविधान का क्या भविष्य होगा? अर्थात् क्या वह इसकी रक्षा कर सकेगा या इसको फिर खो देगा। यह दूसरा विचार है जो उनके मन में उत्पन्न होता है और पहले विचार की भांति व्यथित करता है।

तीसरा प्रश्न था कि संविधान की गुणवत्ता क्या है? डॉ. अम्बेडकर संविधान और राजनीतिक संस्कृति से जोड़ते हैं और कहते हैं, "मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निस्संदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है।" संविधान तो एक मात्र व्यवस्था हैं जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए निर्मित किया गया। संविधान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सामान्य नागरिक किस रूप में इस राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनता है।

डॉ. अम्बेडकर कहीं भी रहे हों, लेकिन उनके हृदय और मस्तिष्क में भारत ही बसता और धड़कता था। इसलिए जब हम डॉ. अम्बेडकर को समग्रता में देखते है तो हमें उनके जीवन की महानता के दर्शन होते हैं। प्रत्येक भारतीय को वे एक सन्देश देते है, "We are Indian Firstly and Lastly" ये पंक्ति पढ़ने में जितनी सामान्य दिखती है इसका अर्थ उतना ही गहरा है

वे भारत के सन्दर्भ में लोकतंत्र और संविधान के सफलता के लिए तीन बात कहते हैं—

1. क्रांति मार्ग को त्यागना,
2. व्यक्ति पूजा से विच्छेदन
3. राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक समाज के साथ समन्वयन।

ये अच्छे शिल्पकार का प्रेम है कि अपने द्वारा निर्मित भवन को देर तक सुरक्षित रखना चाहता है इसलिए उन आशंकाओं का भी समाधान करता है। यहां बाबा साहेब संविधान के भविष्य में आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में संविधान को लचीला रखने के पक्षधर थे, जिसका परिणाम आज देखने को मिलता है, इससे संविधान की सार्थकता व यर्थाथता भी देखने को मिलती है।

नरेन्द्र मोदी जी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार और डॉ. अम्बेडकर

श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रसार व प्रचार के लिए उनके जीवन से सम्बंधित स्थान (जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि) को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। सरकार के निर्देशानुसार 26 नवम्बर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। यह उनके संविधान में योगदान की स्वीकारोक्ति है। पंचतीर्थ समाज के समरसता के प्रतीक के रूप में विकसित किया गया है। एक प्रकार से यह समय संविधान के सम्मान का समय है और वर्तमान सरकार 'मनसा वाचा कर्मणा' तीनों से श्रद्धांजलि दे रही है।

वर्तमान सरकार की मंशा और डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों के समन्वय को समझना हो तो भारत सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला पदम पुरस्कार है। 2015 से लेकर आज तक पदम पुरस्कार प्राप्त करने वाले सामाजिक विन्यास को समझा जाय, तो सरकार ने समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति जो निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है, उन्हें सम्मानित किया है। ■

(लेखक केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं)

बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर: अन्याय, अपमान से न्याय व सम्मान की यात्रा

अर्जुन राम मेघवाल

राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने लोकतंत्र की जननी भारत में संवैधानिक मूल्यों को संयोजित करके उन्हें राष्ट्र की नियमित कार्यशैली में प्रतिस्थापित करने में वास्तुकार की भूमिका का निर्वहन किया था। निजी जीवन की अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठकर उन्होंने देश के करोड़ों लोगों के लिए न्याय, समता, समानता, बंधुत्व और सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में बाबा साहेब ने समाज के शोषितों एवं पीड़ितों के उत्थान व संस्थागत असमानताओं को खत्म करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला बनें।

राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान के बावजूद बाबा साहेब को अपने जीवन काल व महापरिनिर्वाण के बाद भी सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते वो सम्मान व प्रतिष्ठा प्रदान नहीं की, जिसके वह हकदार थे, एक तरह से यह राष्ट्रनायक के साथ विश्वासघात था। राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहेब की विशाल एवं अविस्मरणीय विरासत को गुमनामी के अंधेरे में धकेल कर उन्हें हाशिए पर रखने का काम किया। ऐसा करके कांग्रेस के नेताओं ने न केवल बाबा साहेब के साथ बल्कि उन आदर्शों के साथ भी विश्वासघात किया जिनके वे पक्षधर थे।

दशकों से कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का प्रबल समर्थक होने का दावा किया है, लेकिन कांग्रेस द्वारा सामाजिक न्याय का विरोध करने और उदासीनता बरतने को देखते हुए इस संबंध में कांग्रेस के विचारों की एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। उन्हें सम्मान देने में कांग्रेस की विफलता उनके दृष्टिकोण के साथ कांग्रेस के विश्वासघात को दर्शाती है। वैचारिक दोगलेपन में उलझी कांग्रेस को अब मजबूरी में बाबा साहेब अंबेडकर को याद करना पड़ रहा है। इसी कांग्रेस परिवार ने बाबा साहेब का अपमान करके अपने कृत्यों से लगातार उनकी विरासत को कमजोर किया। यह कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब के प्रति ईर्ष्या का ही परिणाम रहा कि बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद 1990 में भारत रत्न देने में 34 साल की देरी हुई, जबकि इसी परिवार के जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान ही यह पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का तैल चित्र लगाने में कांग्रेस ने अनिच्छा दिखाई और कभी जगह की कमी और प्रोटोकॉल के बहाने सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाने की मांग को बार-बार खारिज किया गया। बाबा साहेब के अनुयायियों की मांग पर 9 अगस्त, 1989 को केन्द्रीय कक्ष में तस्वीर लगाई गई, जिसे बाद में हटा दिया गया। कांग्रेस के इस कृत्य से लाखों अनुयायियों ने स्वयं को ठगा महसूस किया। बाद में भाजपा समर्थित सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 1990 को दोबारा बाबा साहेब का तैल चित्र को सेंट्रल हॉल में लगाया गया। नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं सावधानीपूर्वक समयबद्ध तरीके से संरक्षित की गईं, वहीं बाबा साहेब के जीनवकाल में उपयोग आने वाली वस्तुओं यथा टाइपराइटर, किताबों और अन्य कलाकृतियों को दशकों तक खराब होने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसके संरक्षण का कार्य भी मोदी सरकार द्वारा नागपुर स्थित चिंचौली में डॉ. अंबेडकर सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाकर उनकी शाश्वत विरासत को जीवंत किया जा रहा है।

डॉ. अम्बेडकर की राजनीतिक यात्रा को कांग्रेस द्वारा बार-बार बाधित किया गया, जिससे समाज में बदलाव लाने के बाबासाहेब के इरादे से कांग्रेस की परेशानी का पता चलता है। 1952 के आम चुनावों में बाबा साहेब के संसद हेतु निर्विरोध चुने जाने का समर्थन करने के बजाय कांग्रेस ने उनके खिलाफ श्री नारायण काजोलकर को मैदान में उतारा तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें हराने के लिए प्रचार किया। यह विश्वासघात 1953 में भंडारा उपचुनाव के दौरान भी जारी रहा, जहां कांग्रेस ने बाबा साहेब को फिर से रोकने के लिए श्री वानखेड़े को मैदान में उतारा तथा जनता को भ्रमित करने के लिए दोहरे मतदान करने की प्रक्रिया के संदर्भ में दुष्प्रचार किया। यहां यह जानना बेहद प्रासंगिक है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में कुल खारिज मतपत्रों की संख्या 74,333 थी, लेकिन बाबा साहेब की हार मात्र 14,561 वोटों से हुई थी, जो कि कांग्रेस के सुनियोजित दुष्प्रचार का परिणाम थी।

बाबा साहेब ने आरक्षण को समाज के दलित वर्गों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के एक उपाय के रूप में देखा, लेकिन कांग्रेस ने बार-बार इन उपायों में बाधा डाली। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 27 जून, 1961 को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में आरक्षण को 'योग्यता एवं कार्यकुशलता के लिए हानिकारक' कहते हुए इसकी आलोचना की। नेहरू ने अपनी टिप्पणियों से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली

बुनियादी बाधाओं को अनदेखा किया। काका कालेलकर आयोग की 1955 की सिफारिशें जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनका उत्थान करना था, को भी कांग्रेस के नेतृत्व में इसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंडल आयोग के निष्कर्षों ने सकारात्मक कार्रवाई को अपनाने के प्रति कांग्रेस की अनिच्छा को और उजागर कर दिया। 3 मार्च, 1985 को नवभारत टाइम्स में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए साक्षात्कार में 'आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देने' से संबंधित टिप्पणी भी पूरे हाशिए पर खड़े समुदाय की आत्मा को झकझोर देने वाली थी। जब वी.पी. सिंह की सरकार ने वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं तो तत्कालीन विपक्ष के नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस कदम का पुरजोर विरोध किया और इसे विभाजनकारी और देश की प्रगति को बाधित करने वाला निर्णय करार दिया। आज भी आरक्षण पर कांग्रेस का अंतर्विरोध बरकरार है। श्री राहुल गांधी ने वर्ष 2024 में अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान देते हुए आरक्षण के विषय में सुझाव दिया गया था कि समय आने पर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सब तथ्य कांग्रेस के वैचारिक दोगलेपन व सदियों से शोषण का शिकार रहे अनुसूचित वर्ग के लोगों को दिए गए विशेष अधिकारों के प्रति Selective approach के साथ आरक्षण व्यवस्था के प्रति ऐतिहासिक असुविधा को प्रतिबिंबित करता है।

अक्सर कांग्रेस नेता दावा करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, किंतु यह तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसाकि एडविना माउंटबेटन के एक पत्र से पता चलता है, आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ईमोन डी वलेरा ने इस भूमिका के लिए बाबा साहेब की सिफारिश की थी। उनकी अद्वितीय प्रतिभा और देशभक्ति को पहचानते हुए एडविना ने उन्हें एकमात्र ऐसा नेता माना, जो सभी वर्गों और पंथों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम था। यह कांग्रेस की उदारता नहीं थी, बल्कि कांग्रेस द्वारा अनुसूचित वर्गों को दरकिनार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद बाबा साहेब के असाधारण विचारों और नेतृत्व क्षमता को दिया गया सम्मान था। उनकी नियुक्ति उनकी प्रतिभा और उदात्त नैतिक चरित्र का प्रमाण थी, जो उन्होंने अपने विचारों की प्रबल शक्ति और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अर्जित की थी।

इसके ठीक विपरीत, मोदी सरकार ने बाबा साहेब के सिद्धांतों व आदर्शों पर चलकर सैकड़ों जन-कल्याणकारी योजनाओं को न केवल सफलतम रूप से धरातल पर कार्यान्वित किया, बल्कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर संवेदनशीलता से विचार करके, जिस सम्मान के वे हकदार थे उसे प्रतिस्थापित करने का कार्य किया है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों, पंच तीर्थ यथा जन्म भूमि महू (मध्य प्रदेश), शिक्षा भूमि (लंदन), दीक्षा भूमि (नागपुर), परिनिर्वाण भूमि (दिल्ली) व चैत्य भूमि (मुंबई) का निर्माण किया गया। इसी क्रम में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 से हर वर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संविधान दिवस 2023 के अवसर पर न्याय के सर्वोच्च मंदिर सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलनुमा पोशाक में 7 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर लागू की गई नीतियों के माध्यम से बाबा साहेब के दृष्टिकोण में नई जान फूंक दी है। प्रतीकों से आगे बढ़कर मौजूदा सरकार ने बाबा साहेब के विचारों के अनुरूप समाज में प्रभावी बदलाव लाने के लिए नीतियां लागू की हैं। स्टैंड-अप इंडिया और JAM Trinity (जन धन-आधार-मोबाइल) जैसी पहल निर्भरता और बहिष्कार के दुष्चक्र को समाप्त करते हुए हाशिए पर रह रहे समुदायों के बीच वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की शुरुआत ऐतिहासिक और आर्थिक असमानताओं को ठीक करने की दिशा में मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बाबा साहेब की प्रेरणा से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं के माध्यम से पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अपने समय से बहुत आगे थे, वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जहां न्याय और समानता केवल आकांक्षाएं न हों, बल्कि वास्तविकता बन जाएं। संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में उन्होंने प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय किए, यह सुनिश्चित किया कि कानूनी और संस्थागत ढांचे के माध्यम से प्रणालीगत बाधाओं को खत्म किया जा सके।

मोदी सरकार की पहल सार्थक बदलाव के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। संस्थानों, नागरिक समाज और व्यक्तियों को बाबा साहेब के एक ऐसे राष्ट्र के सपने को साकार करने के प्रयास में शामिल होना चाहिए जहां न्याय, समानता और भाईचारा सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि जीवंत वास्तविकताएं हों।

आज देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा, प्रमुखतः कांग्रेस के द्वारा निजी, स्वार्थ के चलते वोट बैंक की राजनीति के वशीभूत बाबा साहेब के नाम का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सच सबके सामने है कि बाबा साहेब का सम्मान किसने किया और सम्मान देने का कार्य किसने किया। अब समय आ गया है कि बाबा साहेब के विचारों को न केवल शासन में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में पूरी तरह से अपनाया जाए। आइए, हम अपने कार्यों के माध्यम से बाबा साहेब की स्मृति को सम्मानित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आदर्श न्याय और प्रगति की दिशा में भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करें। ■

(लेखक केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं)

प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ है

लाल सिंह आर्य

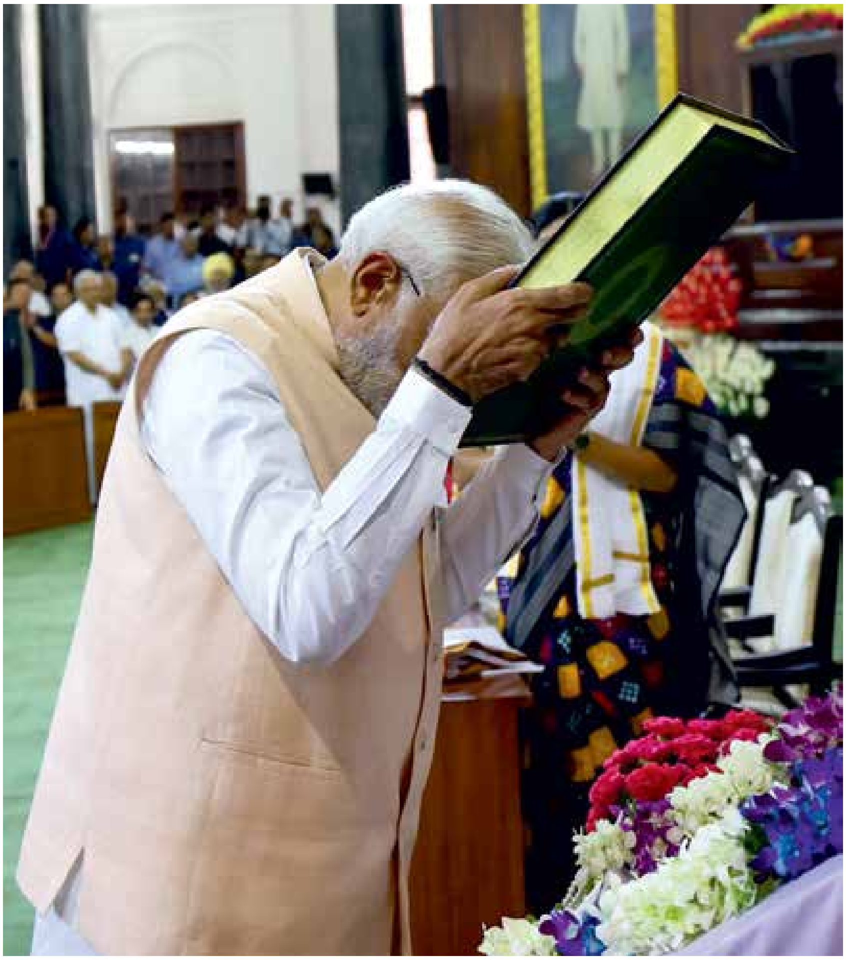

भारतवर्ष का संविधान सभी को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट लिखा है— हम, भारत के लोग... यहां हम और भारत के लोग इन शब्दों में एकत्व की भावना का ज्ञान निहित है। वहीं आगे लिखा है— सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अर्थात् उपयुक्त शब्द भारतवर्ष की विविधता संस्कृति में समरसता की भावना प्रकट करते हैं। यह उद्देशिका स्पष्ट करती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुता के बिना सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए इन सब भावनाओं के साथ हम संविधान को अंगीकृत करते हैं। यह हमारा संविधान ही है जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और अनेक आयामों पर विस्तार से प्रविधान करते हुए नागरिकों की शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान देश की जनता का सुरक्षा कवच है। यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार और कर्तव्यों की सीमाओं का संदेश देता है। यह जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रीयता आदि के भेदभाव से परे सबके लिए समान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जनहितों का सूक्ष्म अध्ययन-विश्लेषण करते हुए ऐसे प्रविधान किए हैं, जिन्हें सभी ने हृदय से स्वीकार किया है। अपने एक वक्तव्य में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि मसौदे में केवल प्रत्येक अनुच्छेद पर ही नहीं वरन् लगभग प्रत्येक वाक्य पर और कभी-कभी तो प्रत्येक अनुच्छेद के प्रत्येक शब्द पर हमें विचार करना पड़ा...। हमने एक लोकतंत्रात्मक संविधान तैयार किया है।

संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे संविधान के मूल आधार को बदला या संशोधित किया जा रहा है? यदि बदला या संशोधित किया जा रहा है तो यह अधिकार किसको है? इसे किस परिस्थिति में बदला या संशोधन किया जा सकता है?

संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था, तो क्या शरीर से आत्मा को हटाया जा सकता है? भारत एक देश है तो फिर 'एक देश, एक संविधान' लागू होना चाहिए या नहीं। क्या संविधान पर धर्म, जाति तथा दलों की इच्छाएं थोपी जा सकती हैं? ये ऐसे ज्वलंत प्रश्न है जिन पर आज विचार करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार निहित स्वार्थों के लिए कुछ लोग अथवा राजनीतिक दल जनता में संविधान को लेकर भ्रम और भय फैलाने का प्रयास करते

हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संविधान जाति, संप्रदाय, धार्मिक मान्यताओं आदि से परे है। संविधान में संशोधन की संसदीय प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया भी किसी व्यक्ति अथवा दल की इच्छा के अनुसार नहीं चलती, बल्कि संसद में चर्चा और पूरी प्रक्रिया के तहत ही होती है।

आजकल विपक्ष के नेता राहुल गांधी पवित्र संविधान को हाथ में लहराकर कि संविधान खत्म हो जाएगा, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आदि बातें कहकर दलितों व आदिवासियों को भड़काने का षड्यंत्र तो करते हैं। राहुल गांधी संविधान को पढ़ते नहीं हैं, उसकी भावना का आदर नहीं करते हैं। वे यह नहीं जानते कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान को अपने हृदय से लगाकर रखा। यदि राहुल गांधी संविधान का सम्मान करते, यदि वे बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का सम्मान करते, यदि वे देश का सम्मान करते और संविधान को मानते तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से गले नहीं मिलते और दंगा भड़काने वालों की पैरवी भी नहीं करते, जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों से नहीं मिलते, गौ-हत्या करने वालों को कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं बनाते और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते। कांग्रेस की संविधान विरोधी कार्य प्रणाली से अब सब परिचित हो चुके हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि इन्होंने जम्मू-कश्मीर में डॉ. अंबेडकर के मना करने के बाद भी धारा 370 लगाकर आदिवासियों का विधानसभा में आरक्षण खत्म करके, 1975 में बेवजह संविधान की आत्मा को कुचलकर देश में आपातकाल लगाने, 90 बार अनुच्छेद 356 लगाकर जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने, जम्मू-कश्मीर में वाल्मीकि समाज को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना आदि कांग्रेस की संविधान विरोधी मानसिकता को सिद्ध करता है।

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तरफ देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि मोदी जी के लिए संविधान एक किताब नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने संविधान व श्रद्धेय बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की भावना का आदर करते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक तरफ संविधान को 'एक देश, एक संविधान' बनाया वहीं दूसरी ओर आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की, 2015 से देश में प्रतिवर्ष शासकीय तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना प्रारंभ करके संविधान के प्रति अपने अटूट सम्मान को दर्शाया है। वे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 'संविधान गौरव यात्रा' निकालकर, संविधान के प्रति अपनी पवित्र निष्ठा दिखा चुके थे।

कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को तो समय-समय पर कुचला ही, उसने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को भी नहीं छोड़ा। यह वही कांग्रेस है जिसने देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष करने वाले महामानव बाबा साहब डॉ. अंबेडकर जी को 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव हरवाया, मतगणना में बड़े स्तर पर घपला किया और डॉ. अंबेडकर को हराने वाले काजोलकर को पद्मभूषण से सम्मानित कर बाबा साहब का अपमान किया

विदित है कि कांग्रेस ने 80 बार संविधान में संशोधन किया और कई बार तो संशोधन जनहित में न होकर अपनी सत्ता बचाने के लिए किया, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य कर दिया था। मोदी जी ने आठ बार संविधान संशोधन दलित, वंचित व पिछड़ों के हितों में किया और दो दिन तक संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा हुई।

कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को तो समय-समय पर कुचला ही, उसने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को भी नहीं छोड़ा। यह वही कांग्रेस है जिसने देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष करने वाले महामानव बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव हरवाया, मतगणना में बड़े स्तर पर घपला किया और डॉ. अंबेडकर को हराने वाले काजोलकर को पद्मभूषण से सम्मानित कर बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, संसद के केंद्रीय कक्ष में उनकी आदमकद तस्वीर नहीं लगाई, देशभर में उनके जीवन से जुड़े स्थलों पर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाए, उनके नाम से किसी योजना का नाम नहीं रखा, और तो और अंतिम समय में दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि भी नसीब नहीं हुई। कांग्रेस के इन पापों से स्पष्ट होता है कि वह बाबा साहेब का राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करना चाहती थी।

एक तरफ कांग्रेस की बाबा साहेब को अपमानित करने की गंदी मानसिकता रही, वहीं दूसरी ओर भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना और उनके सम्मान में जन्म-स्थान महू मध्य प्रदेश, संकल्प भूमि बड़ोदरा, दीक्षाभूमि नागपुर, परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली और चैत्य भूमि (अंतिम संस्कार स्थल) मुंबई में भव्य राष्ट्रीय स्मारकों का निर्माण कराया। इतना ही नहीं लंदन में पढ़ते समय जहां बाबा साहेब किराए के मकान में रहते थे उस मकान को खरीदकर शिक्षा भूमि बनाकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट की। 15 जनपद मार्ग दिल्ली में 192 करोड़ की लागत का श्रद्धेय डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन स्मारकों को ईट-गारे का भवन नहीं, बल्कि इन्हें पंचतीर्थ घोषित कर अपना श्रद्धाभाव प्रकट किया। बाबा साहेब को भारत रत्न दिलाने में व देश की संसद में आदमकद चित्र लगवाने में श्रद्धेय अटल जी व आदरणीय आडवाणी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बाबा साहेब चाहते थे कि देश की एकता, अखंडता और उसे बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व अवसर की समानता यह जाति, धर्म के लोगों का नहीं, बल्कि सभी गरीबों व वंचितों के लिए हो, यह संविधान में भी उल्लिखित किया गया है, लेकिन कांग्रेस केंद्र में लगभग 55 साल और प्रदेशों में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी गरीब और वंचितों को उनके मौलिक अधिकार नहीं दिला पाई। वर्ष 2014 भारत के भाग्य उदय और गरीबों, वंचितों, महिलाओं व श्रमिकों की आशा लेकर आया और भारतीय राजनीति में संकल्प के धनी श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों देश की बागडोर मिली। पिछले 10 वर्षों में आयुष्मान योजना, गरीबों को फ्री अनाज, उज्ज्वला व उजाला योजना, एक देश एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर-घर शौचालय का निर्माण, जनधन योजनाओं ने एक तरफ दलित, आदिवासी, वांछित व अन्य गरीबों के विकास के रास्ते खोले तो दूसरी ओर उनका आर्थिक सशक्तीकरण किया। उच्चतम न्यायालय में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति के जज की नियुक्ति, राष्ट्रपति के पद पर श्री रामनाथ कोविंद जी और आदिवासी समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी का चयन, पहली बार चार प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति, दो प्रदेश मध्यप्रदेश व राजस्थान में उपमुख्यमंत्री व कर्नाटक और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बनाना, केंद्र सरकार में पहली बार 12 अनुसूचित जाति वह आठ अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनाना, आजादी के बाद पहली बार रेलवे बोर्ड के पद पर अनुसूचित जाति व नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर आदिवासी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी की नियुक्ति करके संविधान और राजनीतिक, सामाजिक अवसर की समानता का सम्मान किया।

कांग्रेस ने परिवारवाद की संकुचित मानसिकता के चलते अन्य महापुरुषों व संतों को सम्मान देने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दिया, कुशीनगर से बोधगया होते हुए काशी सारनाथ तक बुद्ध सर्किट बनाने का रास्ता खोल दिया, 100 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रख दी और काशी में उनके जन्म स्थान पर भव्य संत रविदास उद्यान व 25 फुट की बड़ी प्रतिमा स्थापित कर दी। मऊ इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखकर संविधान में उल्लिखित सामाजिक समानता का सम्मान किया, व्यक्ति और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे से बड़े नहीं होते, बल्कि अपनी सोच व ईमानदार प्रयासों से बड़े होते हैं। कांग्रेस ने अपनी संकुचित मानसिकता से अपने आप को बौना बना लिया, उसने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने आप को देश से बड़ा मानकर षड्यंत्र का घर बना लिया, इसलिए आज उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने के कगार पर पहुंच गई है।

कांग्रेस ने परिवारवाद की संकुचित मानसिकता के चलते अन्य महापुरुषों व संतों को सम्मान देने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दिया, कुशीनगर से बोधगया होते हुए काशी सारनाथ तक बुद्ध सर्किट बनाने का रास्ता खोल दिया, 100 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रख दी और काशी में उनके जन्म स्थान पर भव्य संत रविदास उद्यान व 25 फुट की बड़ी प्रतिमा स्थापित कर दी। मऊ इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखकर संविधान में उल्लिखित सामाजिक समानता का सम्मान किया, व्यक्ति और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे से बड़े नहीं होते, बल्कि अपनी सोच व ईमानदार प्रयासों से बड़े होते हैं

भाजपा का लक्ष्य है— अंत्योदय, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश, इसी भावना से राजनीतिक स्वार्थ को अलग रखकर संघर्ष किया, सत्ता के शीर्ष स्थान पर बैठकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत में रहने वाले गरीबों, वंचितों का सशक्तीकरण, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों को ताकतवर बनाने के संकल्प को पूरा करने में दिन रात एक कर दिया। हाल ही में 'मन की बात' के 117वें प्रसारण में उन्होंने संविधान के विषय में कहा कि— हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वह समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है, संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है...। जब संकल्प पवित्र होता है तो लक्ष्य कितने भी कठिन हो प्राप्त होते ही हैं। तमाम नए-नए षड्यंत्र अपमानों के बीच अत्यंत गरीबी में पैदा हुए मोदी जी एक सफल योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि वे विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता हैं। वे जब भी संसद में जाते हैं अथवा अन्य अनेक अवसरों पर संविधान सम्मत स्थानों, व्यक्तियों और संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं। उनके लिए संविधान एक पुस्तक भर नहीं है अपितु वह एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसका वे सदैव प्राणपन से सम्मान करते हैं। ■

(लेखक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माता का अपमान

बृजलाल

भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के पहले से करते रहे। वे नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बनें। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जुलाई, 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अंग्रेजों ने यह चुनाव पूरे अविभाजित भारत में कराए थे, जिसमें भारत के साथ आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, परंतु भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। उस समय 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए 229 सदस्य और 29 रियासतों से 70 सदस्य मनोनीत किए गए थे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर मुम्बई उत्तर से संविधान सभा का चुनाव लड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें किसी भी हालत में संविधान सभा में नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने बांबे प्रेसीडेंसी के प्रधानमंत्री बी.जी. शेखर को बाबा साहेब को चुनाव हरवाने की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर डॉ. अंबेडकर को मुम्बई से संविधान सभा का चुनाव हरवा दिया।

संविधान सभा में बाबा साहेब

संविधान सभा में मुम्बई से बाबा साहेब को हराये जाने के बाद भारत के दलितों में खलबली मच गई। वे निराश थे कि यदि बाबा साहेब संविधान सभा में नहीं पहुंचेंगे तो उनके हितों की रक्षा नहीं हो पायेगी। बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहेब को बंगाल से जीताकर संविधान सभा में भेजने का निर्णय लिया। उन्हें जिताने के लिए 5 विधायकों की आवश्यकता थी। उस समय बंगाल में 4 विधायक अनुसूचित जाति के थे, जीतने के लिए एक और विधायक के समर्थन की आवश्यकता थी, जिसके लिए जोगेन्द्रनाथ मंडल जी- जान से लग गए। 8 जुलाई, 1946 को बाबा साहेब ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनके प्रस्तावक जोगेन्द्रनाथ मंडल और समर्थक नागेन्द्र नारायण राय थे। कांगेस ने यहां भी उन्हें हराने के लिए जोगेन्द्रनाथ मंडल के दार्शनिकगुरु हरिचांद गुरुचांद ठाकुर के वंशज पी.आर. ठाकुर को बाबा साहेब के विरोध में उतार दिया। जोगेन्द्र बाबू ने बाबा साहेब को जिताने के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बड़े भाई शरतचंद्र बोस का सहयोग लिया। बाबा साहेब को जोगेन्द्रनाथ मंडल के अलावा 6 अन्य विधायकों- नागेन्द्र नारायण राय, मुकुंद बिहारी मल्लिक, द्वारिकानाथ बरूरी, गयानाथ बिस्वास, क्षेत्रीनाथ सिंधा और बिरसा का समर्थन मिला और 20 जुलाई, 1946 को बाबा साहेब विजयी घोषित हुए।

बाबा साहेब संविधान सभा से बाहर

बाबा साहेब की जीत की खुशी केवल सालभर रह पाई। 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद में 'भारतीय स्वतंत्रता बिल' प्रस्तुत हुआ, जो 15 जुलाई, 1947 को पारित हो गया। भारत का विभाजन निश्चित हो गया। भारत विभाजन के साथ ही बंगाल भी दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। बाबा साहेब बंगाल के जिस खुलना-जैसोर सीट से निर्वाचित हुए थे, वह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस प्रकार बाबा साहेब भारत की संविधान सभा से बाहर हो गए। दुःखद पक्ष यह रहा कि खुलना-जैसोर क्षेत्र में हिंदू 52 प्रतिशत और मुस्लिम 4 प्रतिशत थे और बंटवारे में सैद्धांतिक रूप से इसे भारत का हिस्सा होना चाहिए था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुटिल राजनीति के तहत उसे पाकिस्तान को दे दिया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुत्सित नीति थी कि बाबा साहेब को स्वतंत्र भारत की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर मुम्बई उत्तर से संविधान सभा का चुनाव लड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें किसी भी हालत में संविधान सभा में नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने बांबे प्रेसीडेंसी के प्रधानमंत्री बी.जी. शेखर को बाबा साहेब को चुनाव हरवाने की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर डॉ. अंबेडकर को मुम्बई से संविधान सभा का चुनाव हरवा दिया

बाबा साहेब संविधान सभा में आए

बाबा साहेब 1942 से 1946 तक 'वायसराय परिषद्' के सदस्य थे उनके पास श्रम और सी.पी.डब्ल्यू.डी. विभाग थे।

वायसराय परिषद् में बाबा साहेब अपनी कार्यकुशलता और विद्वता का परिचय दे चुके थे। बाबा साहेब का जीवन संघर्षभरा था, वे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों के हितों के लिए समर्पित थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लंदन में 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों और पिछड़ों के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की समस्याओं और हितों को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया था। उनके गोलमेज सम्मेलन 1930 के भाषण को ऐतिहासिक माना जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई थी। नेहरूजी नहीं चाहते थे कि दलित, पिछड़े

शेष पृष्ठ २० पर...

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी

नरेन्द्र मोदी

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं... लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं...कितने गूढ़ हैं। अटल जी, कूच से नहीं डरे... उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो ये भी कहते थे... जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है..कौन जानता किधर सवेरा...आज अगर वो हमारे बीच होते, तो वो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था...और जोर से पीठ में धौल जमा दी थी। वो स्नेह...वो अपनत्व...वो प्रेम...मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है।

आज 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने 'भारत रत्न' अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी।

वो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्यूनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही एनडीए ने टेक्नॉलजी को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया।

जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वे चाहते थे भारत के वर्ग, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने।

उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई-भतीजावाद में फंसी

देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनीं, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा।

उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब भी 11 मई, 1998 का वो गौरव दिवस याद है, एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे 'ऑपरेशन शक्ति' का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था, लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो एक अलग मिट्टी से बना है।

उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, ये पुराना भारत नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी थी कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया।

वाजपेयी सरकार के शासन काल में कई

बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं। करगिल युद्ध का दौर आया। संसद पर आतंकियों ने कायरना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत और भारत का हित सर्वोपरि रहा।

जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे, तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनतीं।

कुछ सांसदों की संख्या लेकर भी, वो कांग्रेस की कुनीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया, ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है।

संसद में कहा गया उनका ये वाक्य... सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए...आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

वो भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वो ये भी जानते थे कि लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरूरी है। आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली। जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प दोहराया। एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। वो अनेक दलों को साथ लाए और एनडीए को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया।

पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वो ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।

उन में सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़-तोड़ की राजनीति न चुनकर, इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की।

संविधान के मूल्य संरक्षण में भी उनके जैसा कोई नहीं था। डॉ. श्यामा प्रसाद के निधन का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। वो आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने 'जनसंघ' का जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता दी। मैं जानता हूं कि ये निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन वाजपेयी जी के लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा, संविधान था।

हम सब जानते हैं, अटल जी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने अपनी हिंदी से पूरे देश को खुद से जोड़ा। पहली बार किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया।

राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी वे साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वे एक ऐसे कवि और लेखक थे, जिनके शब्द हर विपरीत स्थिति में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। वे हर उम्र के भारतीय के प्रिय थे, हर वर्ग के अपने थे।

मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। अगर आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका श्रेय उस अटल आधार को है, जिस पर ये दृढ़ संगठन खड़ा है।

बीजेपी की नींव तब रखी, जब कांग्रेस जैसी पार्टी का विकल्प बनना आसान नहीं था। उनका नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दक्षता, साहस और लोकतंत्र के प्रति उनके अगाध समर्पण ने बीजेपी को भारत की लोकप्रिय पार्टी के रूप में प्रशस्त किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया।

जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आईं, उन्होंने सदैव विचारधारा को खुले मन से चुना। वे देश को ये समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में परिणाम दे सकता है।

आज उनका रोपित बीज, एक वटवृक्ष बनकर राष्ट्र सेवा की नव पीढ़ी को रच रहा है। अटल जी की 100वीं जयंती, भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए, हम सब इस अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है, 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही, हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

पृष्ठ 17 का शेष भाग...

और आदिवासियों का प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग ले और कांग्रेस की कुत्सित नीतियों को बेनकाब कर दे।

जनता बाबा साहेब की कार्यकुशलता और विद्वता का सम्मान करती थी और उन्हें संविधान सभा में पहुंचाना चाहती थी, जिससे भारत के संविधान में दलितों/पिछड़ों के हितों की रक्षा हो सके। जनता के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के प्रति अपनी हठधर्मिता नरम की और वे बाम्बे राज्य से मुकुन्द रामराव जानकर द्वारा खाली कराई गई सीट से चुनकर भारतीय संविधान सभा में पहुंचे।

संविधान प्रारूप समिति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 'प्रारूप समिति' थी, जिसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया था। इस समिति को ही नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। नेहरूजी बाबा साहेब को प्रारूप समिति में नहीं देखना चाहते थे। डॉ. अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई थी, परंतु जनता के दबाव के कारण बाबा साहेब संविधान सभा में चयनित हो सके।

पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान लिखने के लिए ब्रिटिश विशेषज्ञ की सहायता लेना चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी ने कहा कि जब भारत में डॉ. अंबेडकर जैसा विद्वान उपलब्ध है तो विदेशी विशेषज्ञ की क्या जरूरत है।

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर बनाए गए। समिति के अन्य सदस्य एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णामाचारी, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान थे।

इन सदस्यों में दो विदेश मे रहे, एक का देहान्त हो गया। कई सदस्यों का वांछित सहयोग नहीं मिला। संविधान पर हस्ताक्षर करते समय प्रारूप समिति के सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी ने स्वीकार किया कि संविधान निर्मित करने में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मुख्य भूमिका रही।

भारत की अंतरिम सरकार 1946

2 सितंबर, 1946 को भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए वायसराय लार्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्य शामिल थे। कांग्रेस के तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल किए गए, तब सदस्यों की कुल संख्या 14 हुई।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 'प्रारूप समिति' थी, जिसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया था। इस समिति को ही नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। नेहरूजी बाबा साहेब को प्रारूप समिति में नहीं देखना चाहते थे। डॉ. अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई थी, परंतु जनता के दबाव के कारण बाबा साहेब संविधान सभा में चयनित हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान लिखने के लिए ब्रिटिश विशेषज्ञ की सहायता लेना चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी ने कहा कि जब भारत में डॉ. अंबेडकर जैसा विद्वान उपलब्ध है तो विदेशी विशेषज्ञ की क्या जरूरत है

अंतरिम सरकार में दो दलित मंत्री शामिल किए गए। ये सदस्य थे बाबू जगजीवन राम—श्रम मंत्री और जोगेन्द्र नाथ मंडल— कानून मंत्री। मंडल मुस्लिम लीग कोटे से बनाये गए थे। अंतरिम सरकार में डॉ. अंबेडकर को नजरंदाज किया गया जिसकी टीस बाबा साहेब को सालती रही। 4 साल एक महीना और 26 दिन बाद भारत के कानून मंत्री के पद से जब 27 सितंबर, 1951 को बाबा साहेब ने त्यागपत्र दिया तो उन्होंने लिखा था कि 1946 की अंतरिम सरकार में उन्हें मंत्री पद लायक नहीं समझा गया।

भारत के कानून मंत्री डॉ. अंबेडकर के पास कोई प्रशासनिक विभाग नहीं

देश की आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें बाबा साहेब कानून मंत्री बनाए गए। बाबा साहेब चाहते थे कि उन्हें कोई प्रशासनिक पद दिया जाए जिससे वे दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए कुछ कर सके। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वायसराय परिषद् का सदस्य होने के कारण वे जानते थे कि कानून मंत्रालय प्रशासनिक दृष्टि से महत्वहीन है। वे इस मंत्रालय को खाली साबुनदान कहते थे, जो केवल पुराने-पुराने वकीलों के खेलने के लिए अच्छा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से कहा कि वायसराय परिषद् की कार्यकारी परिषद् में उनके पास दो प्रशासनिक विभाग 'श्रम और सी.पी.डब्ल्यू.डी.', जहां उन्होंने बहुत सी परियोजनाओं को देखा है, जिसके कारण भी उन्हें कुछ प्रशासनिक विभाग मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री सहमत भी हुए कि वे उन्हें 'योजना' विभाग देंगे जिसका वे सृजन करने वाले हैं। योजना विभाग काफी विलंब से बना और जब बना तो वहां भी बाबा साहेब को अनदेखा कर दिया गया।

उनके कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभाग बदले, कई को दो-तीन विभाग भी सौंपे गए, परंतु नेहरूजी ने उनके नाम पर कभी विचार ही नहीं किया। उन्हें कैबिनेट की मुख्य समितियों- जैसे विदेशी मामले, रक्षा समिति, आर्थिक मामलों की समिति में भी स्थान नहीं दिया गया। बाबा साहेब विख्यात अर्थशास्त्री थे, उन्हें आर्थिक मामलों की समिति में लिए जाने की आशा थी, जो निराशा ही साबित हुई।

नेहरूजी के दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा से बाबा साहेब दुःखी

बाबा साहेब नेहरू सरकार द्वारा दलितों, पिछड़ों, वंचितों की उपेक्षा से दुःखी थे। संविधान में दलितों, पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। इन वर्गों के हितों की रक्षा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी सरकार द्वारा किया जाना था। संविधान लागू होने के एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी सरकार ने आयोग बनाने के बारे में सोचा तक नहीं। 1946 में जब वे किसी पद पर नहीं थे, तब उन्हें दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत चिंता सता रही थी। अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के मामले में अंग्रेजों ने जो वादे किए थे, उनसे भी नेहरू सरकार मुकर गई। अनुसूचित जातियों की स्थिति की रक्षा के लिए संविधान में किए गए प्रावधान से बाबा साहेब संतुष्ट नहीं थे। दलितों पर अत्याचार से बाबा साहेब दुःखी थे, क्योंकि आजादी के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। उन्हें बहुत दुःख हुआ कि दलितों के मुद्दों पर कुछ नहीं हो पा रहा था और वे उपेक्षित थे।

पंडित नेहरू को केवल मुसलमानों की चिंता

स्वतंत्र भारत में दलितों, पिछड़ों की दशा से बाबा साहेब बहुत दुःखी रहते थे। 10 अक्तूबर, 1951 को अपने त्यागपत्र में उन्होंने बड़ी कड़वी सच्चाई लिखी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों के सुरक्षा के लिए समर्पित है। बाबा साहेब ने कहा कि वे चाहते हैं कि मुसलमानों को जब भी और जहां भी जरूरत हो, उन्हें दिया जाए लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है? क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? प्रधानमंत्री ने इन समुदायों के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। देश के इन वंचित समाज को मुसलमानों से अधिक देखभाल की जरूरत है।

हम बाबा साहेब के मुक्त विचारों से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों की शुरुआत से ही विरोधी रही है।

संविधान निर्माता का अपमान

कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहेब को नीचा दिखाने का प्रयास करती रही। उन्हें जीवनपर्यंत उपेक्षा झेलनी पड़ी। उन्हें संविधान सभा में रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। जब बाबा साहेब 1952 में मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़े, तब नेहरूजी ने दो बार उनके चुनाव में जाकर विरोध किया। बाबा साहेब के पूर्व सहयोगी काजोलकर से बाबा साहेब 14,374 वोट से चुनाव हार गए। देखने की बात यह भी है कि उस चुनाव में लगभग 78,000 वोट अवैध घोषित किए गए। इसी प्रकार कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा उपचुनाव में फिर बाबा साहेब को हरवा दिया।

इतना ही नहीं, कांग्रेस बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद भी 'भारत रत्न' तो दूर पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सुझाव पर बाबा साहेब को 'भारत रत्न' दिया गया और 14 अप्रैल, 1990 में सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लग सकी।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर, 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति थी। उनका कहना था कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की कोई आवश्यकता नही हैं। अब संविधान दिवस का आयोजन करके संविधान निर्माता 'भारत रत्न' डॉ. भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया जाता है और संविधान निर्माण में उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है

भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रयास से 'भारत रत्न' तथा बाबा साहेब का सम्मान

वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली, जन्मस्थान महू, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत भूमि इन्दुमिल मुम्बई, उनकी शिक्षा स्थली लंदन, ब्रिटेन में पंचतीर्थ का निर्माण करवाये, जो अब तीर्थस्थली बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बाबा साहेब को केवल अपमानित किया है।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर, 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति थी। उनका कहना था कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अब संविधान दिवस का आयोजन करके संविधान निर्माता 'भारत रत्न' डॉ. भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया जाता है और संविधान निर्माण में उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। ■

(लेखक राज्यसभा सांसद एवं उ.प्र. के पूर्व डीजीपी हैं)

बाबा साहेब और उनके नाम पर की जा रही गांधी परिवार की कुत्सित राजनीति

डॉ. भोला सिंह

डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय समाज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने भारत के दलित, वंचित और पिछड़े समाज को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व और योगदान को लेकर जो राजनीतिक खेल कांग्रेस के द्वारा दशकों से खेला जा रहा है, वह न केवल उनके आदर्शों का अपमान है, बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

इतिहास गवाह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर के योगदान को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लोकसभा चुनाव में जीतने के मार्ग में अनेक नैतिक-अनैतिक बाधाएं खड़ी कीं। यह कटु सत्य है कि नेहरू और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकरजी को मुख्यधारा की राजनीति से अलग-थलग करने के लिए हरसंभव प्रयास किया।

इतना ही नहीं, गांधी-नेहरू परिवार ने स्वयं को भारत रत्न से विभूषित करवा लिया, लेकिन बाबा साहेब को यह सम्मान उनके जीवनकाल में या उसके बाद भी कई दशकों तक नहीं दिया गया। भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार ने अंततः इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया। यह कांग्रेस की वैचारिक संकीर्णता और अवसरवादी राजनीति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। स्वयं को और अपने परिवार को सम्मानित करने वाली कांग्रेस ने बाबा साहेब जैसे महापुरुष को उचित सम्मान देने में कोताही बरती।

कांग्रेस की राजनीति का केंद्रबिंदु केवल सत्ता रही है। दलित और वंचित समाज को उन्होंने केवल एक 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया। बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों के हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा। गांधी-नेहरू परिवार ने बाबा साहेब के योगदान को धूमिल करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की।

ऐसी विषम परिस्थितियों में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने डॉ. अंबेडकर के प्रति सम्मान और समर्थन का परिचय दिया। उनके विचारों को आगे बढ़ाने और दलित समाज को सशक्त बनाने के लिए जनसंघ और आरएसएस ने निरंतर प्रयास किए। यह समर्थन केवल सांकेतिक नहीं था, बल्कि विचारधारा के स्तर पर बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात् करने का प्रयास था। ऐसा उन्होंने कई बार बाबा साहेब के विचारों से सहमति न रखते हुए भी किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को उनके विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय योगदान के अनुरूप सम्मान दिया है। 'पंच तीर्थ' का निर्माण— महू में जन्मस्थली, नागपुर दीक्षाभूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण-भूमि, लंदन में अंबेडकर हाउस और मुंबई में चैत्यभूमि- बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। दिल्ली में अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र और मुंबई में निर्माणाधीन बाबा साहेब की गगनचुंबी मूर्ति मोदी जी के उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।

इसके अतिरिक्त, संविधान दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय बाबा साहेब की स्मृतियों को जीवंत रखने का एक ऐतिहासिक कदम है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने न केवल बाबा साहेब को उचित सम्मान दिया, बल्कि दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू कीं। प्रधानमंत्री मोदीजी ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहेब का सम्मान केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं— जैसेकि

इतिहास गवाह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर के योगदान को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लोकसभा चुनाव में जीतने के मार्ग में अनेक नैतिक-अनैतिक बाधाएं खड़ी कीं। यह कटु सत्य है कि नेहरू और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकरजी को मुख्यधारा की राजनीति से अलग-थलग करने के लिए हरसंभव प्रयास किया। इतना ही नहीं, गांधी-नेहरू परिवार ने स्वयं को भारत रत्न से विभूषित करवा लिया, लेकिन बाबा साहेब को यह सम्मान उनके जीवनकाल में या उसके बाद भी कई दशकों तक नहीं दिया गया

आज जब देश एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक बार फिर बाबा साहेब के नाम पर घृणा और भ्रम का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाहजी के संसद में दिए बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस की कोशिशें यह साबित करती हैं कि यह पार्टी देश में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करती

जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना- दलित और वंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम हैं।

कांग्रेस और गांधी परिवार ने बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे नेता जब दलित समाज के बीच जाते हैं, तब उनके प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव साफ झलकता है। उनकी राजनीति का मकसद केवल दलित वोट बैंक को सुरक्षित करना है, न कि समाज के वास्तविक उत्थान के लिए काम करना।

आज जब देश एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक बार फिर बाबा साहेब के नाम पर घृणा और भ्रम का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाहजी के संसद में दिए बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस की कोशिशें यह साबित करती हैं कि यह पार्टी देश में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करती। कांग्रेस का यह रवैया न केवल दलित समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि देश की अखंडता और शांति के लिए भी खतरा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम और उसके समर्थक बुद्धिजीवी हरसंभव प्रयास कर रहे हैं कि समाज में अस्थिरता बनी रहे। यह केवल राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में वापसी करना है, चाहे इसके लिए उन्हें देश की सामाजिक एकता और शांति को दांव पर क्यों न लगाना पड़े।

यह समय की मांग है कि कांग्रेस और गांधी परिवार की इस विभाजनकारी राजनीति पर स्थायी रोक लगाई जाए। देश को एकजुट रखने और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रों का पर्दाफाश आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात् कर आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित और पिछड़े समाज के सशक्तीकरण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे न केवल बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि हैं, बल्कि एक नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव भी हैं।

अब समय आ गया है कि देश की जनता कांग्रेस और गांधी परिवार की इस घृणित राजनीति को पूरी तरह नकारे और राष्ट्रहित में एकजुट होकर आगे बढ़े। बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी साकार होगा, जब समाज में समानता, न्याय और सद्भावना का वातावरण स्थापित होगा। ■

(लेखक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद हैं)

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बाबा साहेब के विजन को जमीन पर उतारा

गुरु प्रकाश

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था और यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। हमारे देश के संविधान को इस तरह से तैयार किया गया था कि यह न केवल देश के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखे, बल्कि बदलते समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुरूप खुद को अद्यतन करने की क्षमता भी रखे। इसका मूल उद्देश्य हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना था।

संविधान में संशोधन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान (अनुच्छेद 368) रखा गया था, ताकि तेजी से बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके। इसका उद्देश्य केवल संविधान को स्थायित्व देना और उसे बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बनाना था।

हालांकि, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग एक आवश्यक और सकारात्मक कदम के रूप में किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई बार इस्तेमाल किया गया। भारत की आज़ादी के बाद दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने संविधान के संशोधन की शक्ति का उपयोग संविधान के आदर्शों और मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए कम और अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के लिए बड़ी मजबूती से किया। कांग्रेस के इस मनमाने रवैये ने न केवल हमारे देश के संविधान के मूल उद्देश्यों को कमजोर किया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को भी घोर संकट में डाल दिया।

कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किए गए कई संशोधनों, जिसकी संख्या लगभग सैकड़े के आसपास है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान को राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर सिर्फ अपने फायदे के लिए बदलने की प्रवृत्ति थी। इन संशोधनों का उद्देश्य न केवल पार्टी और नेहरू परिवार के पारिवारिक हितों को बढ़ाना था, बल्कि कई बार विपक्षी दलों को दबाने और लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए भी इसका उपयोग किया गया।

कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किए गए कई संशोधनों, जिसकी संख्या लगभग सैकड़े के आसपास है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान को राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर सिर्फ अपने फायदे के लिए बदलने की प्रवृत्ति थी। इन संशोधनों का उद्देश्य न केवल पार्टी और नेहरू परिवार के पारिवारिक हितों को बढ़ाना था, बल्कि कई बार विपक्षी दलों को दबाने और लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए भी इसका उपयोग किया गया। 1951 में किया गया पहला संशोधन इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाए। इस कदम को उस दौर के कई नेताओं ने जनता की आवाज दबाने का प्रयास भी बताया है

1951 में किया गया पहला संशोधन इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाए। इस कदम को उस दौर के कई नेताओं ने जनता की आवाज दबाने का प्रयास भी बताया है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय 'आपातकाल' के दौरान, कांग्रेस ने संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग 1976 के 42वें संशोधन के रूप में किया। इस दौरान किए संशोधनों की संख्या इतनी ज्यादा थी के इसे, 'मिनी संविधान' कहा गया, क्योंकि इसने हमारे देश के संविधान के कई मूलभूत ढांचों को ही बदलकर रख दिया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र को कुचलने का ये प्रयास भारत कभी नहीं भूल सकता, जो इसका गवाह है कि किस हद तक संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा सकता है। 'आपातकाल' लागू होते ही देश में सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म और अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई थी। पूरे देश के विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों के साथ-साथ लाखों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था।

बाबा साहेब ने संविधान को हमारे देश के लोकतंत्र का संरक्षक माना था। उन्होंने

आपातकालीन प्रावधानों को केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए रखा था, न कि सत्ता में बने रहने के लिए। आपातकाल के दौरान इन प्रावधानों के साथ जिस तरह खेला गया, वह उनकी दृष्टि के विपरीत था। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में आपातकालीन प्रावधान इसलिए जोड़ा था, ताकि देश को आंतरिक या बाहरी खतरों से बचाया जा सके। बाबा साहेब ने अपने जीवनकाल में न जाने कितनी यातनाएं, जातिगत भेदभाव और संघर्षों को झेला, फिर भी हमारे संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिले, ऐसी दूरगामी कल्पना कर उसमें समाहित किया। 1975 में लाये गए आपातकाल ने बाबा साहेब के मूलभूत विचार और संविधान की मूल भावना को ही तार-तार कर दिया, ये कांग्रेस का संविधान और देश के लोकतंत्र के प्रति, झूठे नकाब के पीछे छिपा उनका वास्तविक चेहरा दिखाता है।

बाबा साहेब का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। हमारे देश के संविधान शिल्पकार होने के साथ-साथ, उनका जीवन, समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहा। उनकी दी हुई यही विरासत हमारे लोकतान्त्रिक ढांचे का आधार साबित हुई। विडंबना ये रही कि कांग्रेस पार्टी, जिसने दशकों तक भारत पर शासन किया, ने उनके व्यक्तित्व, विरासत और भावना को बार-बार अपमानित किया।

बाबा साहेब को उनके जीवनकाल में उचित मान्यता नहीं मिली। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए सकारात्मक कदमों और आरक्षण की वकालत की, पर कांग्रेस ने इनके उद्देश्यों को हमेशा ठन्डे बस्ते में ही दबाये रखा। बाबा साहेब ने कांग्रेस पर हमेशा यह आरोप लगाया कि यह पार्टी वंचित वर्गों के हितों की अनदेखी करती है। भारत की आज़ादी के समय भी, उनके और कांग्रेस के बीच दलित अधिकारों को लेकर वैचारिक संघर्ष चलता रहा। इतिहास गवाह है, कांग्रेस के दशकों के शासन में वंचित और दलित समुदाय सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर ही रहा और उनको हमेशा की तरह हाशिये पर ही रखा गया।

बाबा साहेब ने संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना था, लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों स्तंभों को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया। राज्यों की चुनी हुई विपक्षी सरकारों को बार-बार अनुच्छेद 356 का उपयोग कर बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस ने संविधान संशोधन का सहारा लिया। कांग्रेस ने संविधान संशोधनों और प्रावधानों का समुचित दुरुपयोग कर सत्ता में बने रहने की कोशिश की और बाबा साहेब के विचारों को बार-बार नजरअंदाज किया।

बात करें बाबा साहेब की विरासत की, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम को खूब भुनाया। बड़े बड़े पोस्टरों पर उनकी तस्वीर लगाई, लेकिन उनके विचारों और सपनों को हकीकत में बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की। सामाजिक न्याय, समान नागरिक संहिता और दलित-वंचितों के अधिकार, ये सब सिर्फ भाषणों तक ही सिमटकर रह गए, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को सच में समझा और उनके विज़न को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। वंचित वर्गों के सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे दिखाते हैं कि बाबा साहेब का सपना सिर्फ एक इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के बदलते भारत का एजेंडा है। यही असली सम्मान है उनकी विरासत का

बाबा साहेब की विरासत को सही मायने में सम्मानित करने का अर्थ केवल उनके नाम का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को नीतियों और शासन में लागू करना है। हमारे देश के लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के सिद्धांतों की रक्षा हो और बाबा साहेब के सपनों का भारत वास्तविकता बने।

हमारे देश का संविधान, जिसे बाबा साहेब ने बड़ी लगन, दूरदर्शिता और वर्षों की तपस्या के बाद तैयार किया था, सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की नींव भी है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस और विपक्षियों ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का ज़रिया बना लिया है। संविधान में संशोधन तो इसलिए होते हैं और होने चाहिए ताकि देश की बदलती ज़रूरतें पूरी की जा सकें, लेकिन कांग्रेस ने इसे सत्ता में बने रहने का टूल भर बना लिया था। 1975 में देश पर थोपा गया 'आपातकाल' और 42वें संशोधन जैसे कदमों ने संविधान के मूल ढांचे पर सीधा हमला किया। मतलब, भारत के संविधान के साथ जैसे चाहा, वैसे खेला।

बात करें बाबा साहेब की विरासत की, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम को खूब भुनाया। बड़े बड़े पोस्टरों पर उनकी तस्वीर लगाई, लेकिन उनके विचारों और सपनों को हकीकत में बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की। सामाजिक न्याय, समान नागरिक संहिता और दलित-वंचितों के अधिकार, ये सब सिर्फ भाषणों तक ही सिमटकर रह गए, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को सच में समझा और उनके विज़न को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। वंचित वर्गों के सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे दिखाते हैं कि बाबा साहेब का सपना सिर्फ एक इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के बदलते भारत का एजेंडा है। यही असली सम्मान है उनकी विरासत का। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

भाजपा डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण की सबसे सच्ची संरक्षक है

अभिनव प्रकाश

बाबासाहेब भीमराव रामजी अंबेडकर का भारत के संवैधानिक ढांचे एवं सामाजिक न्याय के विमर्श में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनके नाम तथा कार्यों को हाशिये पर धकेल दिया गया। कांग्रेस की सरकारों ने समानता एवं समावेशन के उन सिद्धांतों पर बहुत कम ध्यान दिया, जिनका डॉ. अंबेडकर समर्थन करते थे। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देशभर में उचित स्थान प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और पार्टी ने यह भी सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय पर उनके विचार राष्ट्र की नीतियों का मार्गदर्शन करते रहें।

डॉ. अंबेडकर के प्रति कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा उसकी नियति का परिणाम है। कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को संविधान सभा में प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें रोकने का हरसंभव प्रयास किया, यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर की बुद्धिमत्ता एवं सामाजिक स्थिति को अपने राजनीतिक गणित के लिए उचित नहीं माना था। यह उपेक्षा स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। बंगाल के बरिसाल एवं फरीदपुर जैसे क्षेत्रों ने डॉ. अंबेडकर के संविधान सभा में प्रवेश का समर्थन किया था, जिन्हें बाद में इन क्षेत्रों को पाकिस्तान में जाने दिया गया – यह एक ऐसा कदम था जिसने चुनावी लाभ के लिए दलित आबादी वाले क्षेत्रों की उपेक्षा करने वाले कांग्रेसी चरित्र को लोगों के सामने ला दिया था।

कांग्रेस ने बार-बार डॉ. अंबेडकर को चुनावी राजनीति से बाहर करने के लिए रणनीतिक गठबंधन किए। 1952 के लोकसभा चुनावों में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब एस.के. पाटिल सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने नेहरू के निर्देश पर डॉ. अंबेडकर को हराने के लिए कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिला लिया। 1954 में एक बार फिर यह दुश्मनी उजागर हुई, जब पार्टी ने भंडारा उपचुनाव में उन्हें हराने के लिए उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से प्रचार किया, जो इस बात का उदाहरण था कि कांग्रेस अपने वर्चस्व को मिलने वाली किसी भी चुनौती को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प थी— खासकर डॉ. अंबेडकर जैसी क्षमता वाले विचारक से मिल रही चुनौती तो उनके लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकती थी।

> **डॉ. अंबेडकर का नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्यकाल भी उनके प्रति कांग्रेस की उपेक्षा को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर आर्थिक नीति, रक्षा एवं विदेश मामलों पर प्रमुख निर्णय लेने वाली समितियों से बाहर रखा गया। डॉ. अंबेडकर का इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व की जातिगत समस्याओं से लड़ने की अनिच्छा एवं हिंदू कोड बिल जैसे मजबूत सुधारों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की कमी का एक सशक्त उदाहरण था**

डॉ. अंबेडकर का नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्यकाल भी उनके प्रति कांग्रेस की उपेक्षा को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर आर्थिक नीति, रक्षा एवं विदेश मामलों पर प्रमुख निर्णय लेने वाली समितियों से बाहर रखा गया। डॉ. अंबेडकर का इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व की जातिगत समस्याओं से लड़ने की अनिच्छा एवं हिंदू कोड बिल जैसे मजबूत सुधारों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की कमी का एक सशक्त उदाहरण था। इससे भी बदतर यह है कि कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को संगृहीत करना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि पार्टी डॉ. अंबेडकर और उनकी असहमति को आधिकारिक रिकॉर्ड में भी स्थान नहीं देना चाहती थी।

डॉ. अंबेडकर के महान योगदान के प्रति कांग्रेस की उपेक्षा उनके जीवन के साथ ही समाप्त नहीं हुई। दिसंबर, 1956 में उनके महापरिनिर्वाण के बाद तत्कालीन सरकार ने दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस की असुरक्षाओं को दर्शाता है। उनके परिवार को बुनियादी शिष्टाचार से वंचित रखा गया, उन्हें बिना किसी आधिकारिक सहायता के उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए मजबूर किया गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इस यात्रा के लिए राज्य विमान आवंटित करने से इनकार कर दिया गया और डॉ. अंबेडकर की शोकाकुल पत्नी को इस उड़ान की लागत का भुगतान तक करना पड़ा।

इसके बाद के दशकों में कांग्रेस ने नेहरू-गांधी परिवार को भरपूर याद किया, लेकिन डॉ. अंबेडकर को सम्मानित करने के आह्वान को बार-बार नजरअंदाज किया। कांग्रेस की सरकारों में उनकी स्मृति को समर्पित स्मारक, सिर्फ एक स्थल बनकर रह गए। 1990 में भाजपा समर्थित गैर-कांग्रेसी सरकार के तहत ही डॉ. अंबेडकर को मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया— एक ऐसा सम्मान जिसे कांग्रेस ने लगातार रोके रखा।

भाजपा ने भारत के संवैधानिक मूल्यों को आकार देने में डॉ. अंबेडकर की परिवर्तनकारी भूमिका को मान्यता देते हुए उनकी सही विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'पंचतीर्थ' पहल अपने आप में उल्लेखनीय है: यह डॉ. अंबेडकर के जीवन एवं शिक्षा से जुड़े पांच स्थल है— महू में उनका जन्मस्थान, लंदन में उनकी पढ़ाई का स्थान, नागपुर में उनका बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि। इन जगहों को राष्ट्रीय स्मारक बनाकर, भाजपा ने भारत की वास्तविक सामाजिक न्याय की यात्रा में एक मार्गदर्शक के रूप में डॉ. अंबेडकर के स्थान को रेखांकित किया है।

यह परियोजनाएं महज एक प्रतीकात्मकता कदम से कहीं अधिक समानता एवं समावेश के उनके सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। डॉ. अंबेडकर की विरासत को सम्मान देने के लिए बनाया गया 'भीम ऐप' प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय समावेशन पर भाजपा के जोर को दर्शाता है। इसी तरह स्टैंड-अप इंडिया एवं मुद्रा जैसी योजनाएं डॉ. अंबेडकर की उस अर्थव्यवस्था के सपने को प्रतिध्वनित करती हैं, जो वंचितों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती है। दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना एवं उनके लंदन निवास का संरक्षण, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी अंतर्दृष्टि को सुलभ बनाए रखने के लिए भाजपा के समर्पण का प्रमाण हैं।

डॉ. अंबेडकर के भाषणों एवं लेखों में कांग्रेस के दोहरे चरित्र के प्रति बाबासाहेब की गहरी हताशा का एक स्पष्ट संदेश मिलता है। एक ओर जहां उन्होंने पार्टी में जड़ जमाए चाटुकारों को खत्म करने की अनिच्छा को इंगित किया, वहीं कांग्रेस नेताओं पर दलितों के हित के लिए केवल दिखावा करने और उनके उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप भी लगाया। उनकी आलोचनाएं, जिन्हें अक्सर व्यक्तिगत शिकायतों के रूप में खारिज कर दिया जाता है, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक अभिजात्य वर्ग देश में हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ सत्ता साझा करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।

डॉ. अंबेडकर को उनका उचित स्थान प्रदान कर, भाजपा ने एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा है। उनके योगदान को केवल प्रतिमाओं और प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि तक सीमित रखने के बजाय पार्टी ने उनके जीवन को भारत के शासन के ताने-बाने में पिरोया है, उनके सिद्धांतों को स्पष्ट से रखा है— चाहे वह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की बात हो या सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की – जो महज बयानबाजी से कहीं अधिक गहरी प्रतिबद्धता को दिखाती है

यह वैचारिक दरार आज भी कायम है। कांग्रेस कभी-कभार डॉ. अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन यह वास्तविक इरादे से इतर एक अवसरवादी इशारा लगता है। इसके विपरीत, भाजपा ने डॉ. अंबेडकर के मूल्यों को सत्ता के ढांचे में एकीकृत करने का एक सुसंगत मार्ग अपनाया है, विकास योजनाओं को उनके द्वारा समर्थित सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन के सिद्धांतों के साथ जोड़ा है।

शायद डॉ. अंबेडकर के विचारों की पुनः स्थापना का सबसे बड़ा प्रमाण भाजपा के नेतृत्व में हुए मूर्त परिवर्तन में निहित है। जहां कांग्रेस प्रतीकात्मक दिखावे से आगे बढ़ने में विफल रही, वहीं भाजपा ने सामाजिक न्याय एवं हाशिए पर पड़े लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण के उनके आदर्शों को नीति-निर्माण के केंद्र में रखा है, जिससे वैचारिक, क्षेत्रीय एवं सामाजिक विभाजन को पाटा जा सके।

डॉ. अंबेडकर को उनका उचित स्थान प्रदान कर, भाजपा ने एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा है। उनके योगदान को केवल प्रतिमाओं और प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि तक सीमित रखने के बजाय पार्टी ने उनके जीवन को भारत के शासन के ताने-बाने में पिरोया है, उनके सिद्धांतों को स्पष्ट से रखा है— चाहे वह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की बात हो या सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की – जो महज बयानबाजी से कहीं अधिक गहरी प्रतिबद्धता को दिखाती है।

अंत में डॉ. अंबेडकर की कहानी व्यक्तिगत उपलब्धियों के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। यह एक ऐसे राष्ट्र के लिए नैतिक दिशा-निर्देश है जो अभी भी सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है। उनका जीवन और न्याय के लिए संघर्ष अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करते आये हैं और भाजपा की पहलों ने इसको लेकर एक स्पष्ट आह्वान किया है। डॉ. अंबेडकर की भावनाओं को साथ लिए बिना कोई भी भारत के संविधान या समानता की खोज के बारे में बात नहीं कर सकता। कर्तव्यनिष्ठ नीतियों एवं अटूट संकल्प के माध्यम से भाजपा उनके दृष्टिकोण की सबसे सच्ची संरक्षक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली एक जीवंत शक्ति बनी रहे। ■

(लेखक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया

देश के लिए जीने वाला हर बच्चा और युवा 'वीर बालक' है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया। तीसरे वीर बाल दिवस आयोजन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान की याद में वीर बाल दिवस की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह दिन अब करोड़ों भारतीयों के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बन गया है और इस दिन ने कई बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस के लिए प्रेरित किया है।

वीर साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज के युवाओं के लिए उनकी वीरता की गाथा को जानना आवश्यक है और इसलिए उन घटनाओं को याद करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तीन शताब्दी पहले आज ही के दिन वीर साहिबजादों ने बाल्यावस्था में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिब जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह में बाल्यावस्था में ही अपार साहस था। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने मुगल सल्तनत के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया, सभी अत्याचारों को सहन किया और वजीर खान द्वारा दिए गए मृत्युदंड को पूरी बहादुरी के साथ स्वीकार किया।

मुख्य बातें

- 'वीर बाल दिवस' पर हम साहिबजादों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं, हम माता गुजरी जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देते हैं
- साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह में बाल्यवस्था में ही अदम्य साहस था
- समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, देश और उसके हितों से बड़ा कुछ नहीं है
- हमारे लोकतंत्र की विशालता गुरुओं की शिक्षाओं, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है
- इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक युवाओं ने हमेशा भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाई है
- अब, केवल सर्वश्रेष्ठ ही हमारा मानक होना चाहिए

राष्ट्र और राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं है

श्री मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता की याद दिलाई और यह वीरता हमारी आस्था की आध्यात्मिक ताकत थी। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति देने का विकल्प चुना और आस्था के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, राष्ट्र और राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, "देश के लिए किया गया हर काम वीरता का कार्य है और देश के लिए जीने वाला हर बच्चा और युवा 'वीर बालक' है।"

श्री मोदी ने कहा, "अतीत से लेकर आज तक युवाओं की ऊर्जा ने भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी के आंदोलनों तक भारतीय युवाओं ने हर क्रांति में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि युवा शक्ति के कारण ही दुनिया भारत की ओर आशा और उम्मीदों से देखती है।

श्री मोदी ने कहा, "वीर बाल दिवस हमें प्रेरणा से भर देता है और हमें नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब हमारा मानक सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपने-अपने क्षेत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने कहा कि हर युग में देश के युवाओं को देश की नियति बदलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय युवाओं ने विदेशी सत्ता के अहंकार को तोड़कर अपने लक्ष्य हासिल किए, जबकि आज युवाओं के सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों में तीव्र विकास की नींव रखनी चाहिए। ■

किसानों को किफायती दरों पर डीएपी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु एनबीएस सब्सिडी के परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी को किसानों को किफायती दरों पर डीएपी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1 जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी के परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 3,850 करोड़ रुपये होगी।

उल्लेखनीय है कि उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित है। किसानों के कल्याण को दृढ़ता से ध्यान में रखकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखते हुए सरकार ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमत में कोई बदलाव नहीं करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। भू-राजनीतिक बाधाओं और वैश्विक बाजार स्थितियों की अस्थिरता के बावजूद सरकार ने खरीफ और रबी 2024-25 के लिए किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसान हितैषी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी।

जुलाई, 2024 में कैबिनेट ने 01.04.2024 से 31.12.2024 तक एनबीएस सब्सिडी के परे डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव था। कैबिनेट ने एक जनवरी को हुई अपनी बैठक में डीएपी पर विशेष पैकेज को वित्तीय प्रभाव के साथ लगभग 3850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अप्रैल, 2024 से डीएपी के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज की कुल राशि 6,475 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी, ताकि किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

लाभ: किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य: किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी उर्वरक की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंजूर एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से विशेष पैकेज 01.01.2025 से अगले आदेश तक प्रदान किया जाएगा।

2025 की पहली कैबिनेट बैठक हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के आलोक में एक जनवरी को दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, "हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है, जो हमारे देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।" ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुविधाओं/प्रावधानों में संशोधन/समावेश तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को नहीं रोके जा सकने योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के समावेश, जिससे बेहतर पारदर्शिता और दावों की गणना एवं निपटारे में आसानी सुनिश्चित होती है, हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की निधि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी (एफआईएटी) के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

इस फंड का उपयोग इस योजना के तहत यस-टेक, विंड्स आदि जैसे तकनीकी पहलों के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत की भारिता (वेटेज) के साथ उपज के अनुमान हेतु रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। वर्तमान में नौ प्रमुख राज्य (यानी आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक) इसे लागू कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी इस प्रक्रिया में तेजी से शामिल किया जा रहा है। यस-टेक के व्यापक कार्यान्वयन के साथ फसल काटने से जुड़े प्रयोग और संबंधित मुद्दे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे। यस-टेक के तहत 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने शत-प्रतिशत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान की प्रक्रिया को अपनाया है। ■

मनमोहन सिंह जी के निधन पर घटिया राजनीति कर रही कांग्रेस : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 दिसंबर, 2024 को कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि ये वास्तव में विडंबना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय मनमोहन सिंह जी के दुःखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस की इस निम्न स्तर की सोच की जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

कांग्रेस, जिसने डॉ. मनमोहन सिंह जी को जीते जी कभी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी के ऊपर सुपर पीएम के रूप में सोनिया गांधी जी को बिठाकर पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया था, उसे नीचा दिखाया था

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस, जिसने डॉ. मनमोहन सिंह जी को जीते जी कभी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी के ऊपर सुपर पीएम के रूप में सोनिया गांधी जी को बिठाकर पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया था, उसे नीचा दिखाया था। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़कर किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किसी भी बड़े नेता को न तो सम्मान दिया और न ही उनके साथ न्याय किया, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से हों या विपक्ष से हों। चाहे वे बाबासाहेब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लालबहादुर शास्त्री जी हों, पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या अन्य दूसरे बड़े नेता क्यों न हों- कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव इनका अपमान ही किया। कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान के बाद भी उनका अनवरत अपमान किया, इसके कई उदाहरण मौजूद हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि पूर्व पीएम आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। वैसे कांग्रेस का इतिहास याद रखने की जरूरत है। 23 दिसंबर, 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गयी थी, लेकिन सुपर पीएम सोनिया गांधी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में जगह तक नहीं दी गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और बाद में उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी थे, जिन्होंने 2015 में नरसिम्हा राव जी के लिए समाधि भी बनवाया और 2024 में 'भारत रत्न' देकर उनका मान बढ़ाया, उन्हें सम्मान दिया।

उन्होंने कहा कि जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ तो कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा शोक-सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई गई। कांग्रेस को याद हो या न हो, लेकिन उनकी याद्दाश्त के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 'राष्ट्रीय स्मृति' बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी व्यक्तित्व के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा।

उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों के कृतित्व को याद रखने और उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के लिए स्मारक और समाधियां बनवाईं। सम्मान का असली मतलब सीखना है तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सीखें।

श्री नड्डा ने कहा कि एक अनुमान की मानें तो कांग्रेस सरकारों द्वारा देश में करीब 600 सरकारी योजनाओं, शिक्षण संस्थानों, अवार्डों, सड़कों, नेशनल पार्कों, म्यूजियमों, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, इमारतों और खेलों के नाम नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जबकि बाकी शख्सियतों के नाम पर योजनायें केवल ऊंगली पर गिनने लायक ही हैं। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ़ भी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खरगे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। ■

मोदी स्टोरी

नरेन्द्र मोदी का माइक्रो कंप्यूटर

—गोकुल कुन्नाथ, एनआरआई-अटलांटा, यूएसए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा से ही तकनीक की ताकत में दृढ़ता से विश्वास रखते आये हैं। 1990 के दशक में भी उन्हें पता था कि तकनीक जीवन को आसान एवं अधिक व्यवस्थित बना सकती है। वह निजी उपयोग के लिए जहां इसकी प्रशंसा करते थे, वही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका पर भी बात करते थे।

1997 में जब श्री मोदी अमेरिका गए थे, तो उनके मेजबानों ने तकनीक के प्रति उनके आकर्षण को महसूस किया। इस दौरान श्री नरेन्द्र मोदी अटलांटा में रहने वाले एनआरआई व्यवसायी श्री गोकुल कुन्नाथ के घर पर रुके थे। श्री कुन्नाथ याद करते हैं कि उन्होंने जब श्री मोदी से पूछा कि क्या उन्हें अमेरिका से कुछ चाहिए, तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री मोदी ने सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा उन्हें एक माइक्रो कंप्यूटर चाहिए।

यह डिवाइस 3,000-4,000 नाम, फोन नंबर और पते स्टोर कर सकती थी। तब भी श्री नरेन्द्र मोदी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि कैसे तकनीक उन्हें भाजपा के भीतर अपने काम को व्यवस्थित करने और आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

तासासो युन

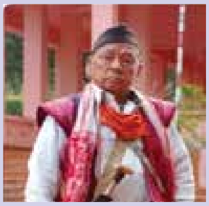

तासासो युन
जन्म: 02 दिसंबर, 1940
सक्रिय वर्ष: 1965-1985
जिला: लोहीत, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के श्री तासासो युन 25 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीपीवी) में शामिल हुए थे। वह वर्ष 1965 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उन्होंने 6 अगस्त, 1967 को जनसंघ पार्टी की एक बैठक में स्वेच्छा से भाग लिया और 1 फरवरी, 1981 को माटुंगा, बॉम्बे में भाजपा में शामिल हो गए। श्री तासासो युन ने 15 वर्षों तक जिला परिषद् सदस्य के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। 2 दिसंबर, 1985 को श्री युन गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सदस्य बने। ■

डॉ. सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों से उबरकर ऊंचाइयों को प्राप्त करना सिखाता है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 दिसंबर को नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह का निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है और विभाजन के दौरान भारत आने के बाद बहुत कुछ खोने के बावजूद डॉ. सिंह एक सफल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों को सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाए।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि डॉ. सिंह को हमेशा एक दयालु व्यक्ति, एक विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में विभिन्न स्तरों पर भारत सरकार में डॉ. सिंह के कई योगदानों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में डॉ. सिंह की भूमिका की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को वित्तीय संकट से निकालकर एक नए आर्थिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और प्रगति में डॉ. सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों और देश के विकास के प्रति डॉ. सिंह की प्रतिबद्धता को हमेशा उच्च सम्मान दिया गया।

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि डॉ. सिंह का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। उन्होंने डॉ. सिंह का विशिष्ट संसदीय करियर उनकी विनम्रता, सौम्यता और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि इस वर्ष की शुरुआत में राज्यसभा में डॉ. सिंह के कार्यकाल के अंत में भी उन्होंने डॉ. सिंह के समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें सभी के लिए प्रेरणास्रोत बताया था। अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद डॉ. सिंह ने व्हीलचेयर पर बैठकर महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लिया और अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की

श्री मोदी ने कहा कि प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने और शीर्ष सरकारी पदों पर रहने के बावजूद डॉ. सिंह ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह हमेशा दलीय राजनीति से ऊपर रहे, सभी दलों के लोगों से संपर्क बनाए रखा और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहे। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के समय और बाद में दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर डॉ. सिंह के साथ अपनी स्वतंत्र चर्चा को याद किया। उन्होंने डॉ. सिंह के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ■

दिल्ली विधानसभा चुनाव: 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को परिणाम

चुनाव आयोग ने 07 जनवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी में 5 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने का आंकड़ा 36 है।

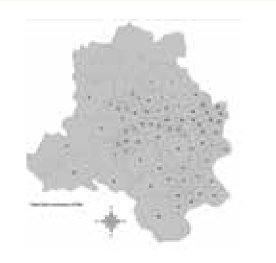

चुनाव आयोग ने दिल्ली के लिए नई संशोधित मतदाता सूची जारी की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में मतदाता आधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर, 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या 1,53,57,529 थी। हालांकि, संक्षिप्त संशोधन के बाद यह संख्या बढ़कर 1,55,24,858 हो गई है, जिसमें दिसंबर, 2024 तक 1,67,329 नए मतदाता जुड़े हैं। ■

हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ होता है: नरेन्द्र मोदी

पहली बार देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बनेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 दिसंबर को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 117वीं कड़ी में कहा कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है। कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेक अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है।

श्री मोदी ने कहा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा।

कुंभ में कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है

उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हों, तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आयें। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। श्री मोदी ने कहा कि अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा... महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा...गंगा की अविरल धारा, न बंटे समाज हमारा।

डिजिटल महाकुंभ

श्री मोदी ने कहा कि इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आप अलग-अलग घाटों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों तक पहुंच सकेंगे। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग स्थलों तक पहुंचने में भी मदद करेगा। कुंभ आयोजन में पहली बार एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई चैटबॉट के ज़रिए कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यक्ति इस चैटबॉट के माध्यम से टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे आज भारतीय संस्कृति की चमक दुनिया के कोने-कोने में फैल रही है। उन्होंने ताजमहल की एक शानदार पेंटिंग का जिक्र किया, जिसे मिस्र की एक 13 वर्षीय दिव्यांग लड़की ने अपने मुख से बनाया है। श्री मोदी ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले मिस्र के लगभग 23 हजार छात्रों ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें उन्हें भारतीय संस्कृति और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती पेंटिंग बनानी थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रचनात्मकता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी।

मलेरिया के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी

श्री मोदी ने मलेरिया और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये दोनों उपलब्धियां आज दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में वर्ष 2015 और वर्ष 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में 80 प्रतिशत की कमी आई है।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई पर श्री मोदी ने विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक अध्ययन का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कैंसर रोगियों को 30 दिनों के अंदर समय पर उपचार सुनिश्चित करने में 'आयुष्मान भारत योजना' की भूमिका पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से 90 प्रतिशत कैंसर रोगी समय पर अपना इलाज शुरू कर पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे की कमी के कारण गरीब मरीज कैंसर की जांच और उसके इलाज से कतराते थे। अब 'आयुष्मान भारत योजना' उनके लिए बड़ा सहारा बन गई है। अब वे अपना इलाज कराने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है।

श्री मोदी ने 'मन की बात' के अंत में कहा कि हमारा भारत, विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य हो या शिक्षा – हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने एक परिवार की तरह मिलकर हर चुनौती का सामना किया और नई सफलताएं हासिल कीं। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जयंती पर 25 दिसंबर को दिल्ली स्थित 'सदैव अटल' पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................... दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।

मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

खजुराहो (मध्य प्रदेश) में 25 दिसंबर, 2024 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन एवं शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 26 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 03 जनवरी, 2025 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन एवं शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में 08 जनवरी, 2025 को विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

साहिबाबाद (गाजियाबाद)आरआरटीएस स्टेशन से नई दिल्ली स्थित न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन तक 05 जनवरी, 2025 को 'नमो भारत ट्रेन' की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 04 जनवरी, 2024 को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्‌घाटन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh | @KamalSandesh
kamal.sandesh | KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 21 जनवरी, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह